5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 1

GHAR Paint.com

सारा सच

दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

PU | DUCO | Painting
Ghar Paint
Call: 99111 14332
www.gharpaint.com

◆ वर्ष : 8 ◆ अंक : 33 ◆ वीरवार 5 मार्च से 11 मार्च , 2026 ◆ पृष्ठ:8 ◆ मूल्य: 3 रुपए, ◆ हिजरी 1446 R.N.I. No. DELHIN/2018/76166 www.sarasach.com

एक नजर

सोनिया गांधी के लेख पर तारीक अनवर का समर्थन

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बुधवार को पार्टी नेता और सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पश्चिम एशिया संघर्ष पर लिखे हालिया लेख का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं। अनवर ने कहा कि सोनिया जी का लेख बिल्कुल सही है। यह एक सुव्यवस्थित और संतुलित लेख है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर भारत का जो रुख हुआ करता था, वह अब नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि हम सच बोलने से कतरा रहे हैं।हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी के लेख पर हमला करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय नीति का मामला है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने मंगलवार को सोनिया गांधी के लेख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि भारत को इस मुद्दे पर टिप्पणी क्यों करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में क्यों बोलना है?

कांग्रेस ने बीजेपी पर शराब माफिया उपहार देने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। इस साल होली पर शराब की दुकानें खुलने के साथ ही, कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली में भाजपा सरकार पर शराब माफिया को उपहार देने का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। यह आरोप दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के कुछ दिनों बाद आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई (बरी होने) पर भाजपा ने शराब माफिया को उपहार दे दिया है। दिल्ली में होली के दिन कभी शराब नहीं बिकती थी... लेकिन आज होली है, सब लोग खुशी से होली मना रहे हैं, भाजपा भी होली मना रही है और अपने वादे पूरे कर रही है। इस साल जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, होली अब ड्राई डे की सूची में नहीं है, इसलिए दिल्ली में होली के अवसर पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। उत्सव में और अधिक उत्साह जोड़ने के लिए लोग शराब की दुकानों के बाहर जमा हो गए। एक ग्राहक ने कहा कि हम त्योहार अच्छे से मनाएंगे।

पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है : राजनाथ

पश्चिम बंगाल (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक देश, एक विधान, एक निशान' का नारा लगाते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने का आग्रह किया। परिवर्तन यात्रा में सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है, जिसे उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी लाएगी। उन्होंने कहा कि यह रैली पश्चिम बंगाल की परिवर्तन की घोषणा है।

सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल वीरों और क्रांतिकारियों की भूमि है, और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित बंगाली परिवर्तनकर्ताओं के योगदान को रेखांकित किया।

रक्षा मंत्री ने कहा कि बंगाल की मिट्टी में त्याग और आत्मसम्मान समाहित है। मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि 'परिवर्तन' की घोषणा बंगाल की धरती से हो। मैं कहना चाहता हूं कि परिवर्तन का समय आ गया

'एक देश, एक विधान, एक निशान' का नारा लगाया

है। अब छुकना मत। मैं इसे रैली नहीं मानता, मैं इसे बंगाल में परिवर्तन की घोषणा मानता हूं।

उन्होंने आगे कहा कि यह वीरों की भूमि है। यह क्रांतिकारियों की भूमि है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। उन्होंने कहा था, श्मुझे रक्त दो, और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। बंगाल की भूमि साधारण नहीं है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस देश में 'दो विधान', 'दो निशान' और 'दो प्रधान' नहीं चलेंगे। उस समय उन्होंने जो नारा लगाया था, वह मात्र नारा नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब इस देश में 'दो विधान', 'दो निशान' और दो प्रधान कभी नहीं होंगे। यहाँ 'एक देश, एक विधान, एक निशान' होगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में कहा था कि दो संविधान (विधान), दो शीर्ष प्रमुख (प्रधान) और दो ध्वज (निशान) का दोहरापन नहीं हो सकता।

इससे पहले दिन में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि परिवर्तन शब्द पश्चिम बंगाल को घुसपैठ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और तृणमूल कांग्रेस सरकार को भाजपा सरकार से बदलने की इच्छा को दर्शाता है।

MBBS डॉक्टर्स व बुद्धिजीवियों को करेंगे सम्मानित

सारा सच (दिल्ली) जमात–ए–सिद्दीकी ऑफ इंडिया (JSI) मनिहार, शीशगर, चूड़ीहार समुदाय के 50 से ज़्यादा जाने–माने डॉक्टरों (MBBS) और बुद्धिजीवियों को सम्मानित करने के लिए एक राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह आयोजित कर रही है, जिन्होंने अपनी पेशेवर उत्कृष्टता और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

यह सम्मान समारोह 26 अप्रैल 2026 को राजा राम मोहन रॉय मेमोरियल हॉल, विष्णु दिगंबर मार्ग, ITO, नई दिल्ली में दोपहर 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जमात–ए–सिद्दीकी ऑफ इंडिया (JSI) उन डॉक्टरों के लिए नामांकन आमंत्रित करती है जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय सेवा की है। प्रत्येक नामांकन में नामांकित व्यक्ति की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल शामिल होनी चाहिए। जमात–ए–सिद्दीकी ऑफ इंडिया (JSI) द्वारा गठित एक चयन समिति पुरस्कार विजेताओं के नामों को अंतिम रूप देगी। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 है ईमेल और डाक द्वारा।

वेस्ट एशिया संकट: भारतीयों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में लगभग एक करोड़ भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा व कल्याण नयी दिल्ली के लिए "सर्वोच्च प्राथमिकता" है। ईरान–अमेरिका संघर्ष के बीच, ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सैकड़ों भारतीय छात्रों को तेहरान से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया, "पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस पर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक संपर्क किया जा सकता है।" अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए थे जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई। इसके बाद ईरान ने इजराइल के साथ ही कई खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में करीब एक करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं और "उनकी सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। हम ऐसे किसी भी घटनाक्रम के प्रति उदासीन नहीं रह सकते जो उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करे।

सोनिया गांधी और राहुल ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या और पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दोनों ने कहा है कि यह समय चुप्पी का नहीं, बल्कि स्पष्ट और नैतिक रुख अपनाने का है। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में लिखे आलेख के माध्यम से और राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार की विदेश नीति पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं।

सोनिया गांधी के आलेख का जिक्र करें तो आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अमेरिका और इज़राइल

❐ विदेश नीति पर घिरी केंद्र सरकार

द्वारा किए गए लक्षित हमलों में हत्या कर दी गई। किसी संप्रभु राष्ट्र के वर्तमान प्रमुख की, वह भी चल रही कूटनीतिक वार्ताओं के बीच, इस प्रकार हत्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर झटका है। सोनिया गांधी ने इसे "अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का खतरनाक क्षरण" बताया है। भारत की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने न तो इस हत्या की स्पष्ट शब्दों में निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर ठोस प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभिक बयान में ईरान की जवाबी कार्रवाई की आलोचना तो की, लेकिन उससे पहले हुए हमलों पर सीधी टिप्पणी से परहेज़ किया। उनके अनुसार, "जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की लक्षित हत्या पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से स्पष्ट और सिद्धांत आधारित प्रतिक्रिया नहीं आती, तो यह हमारी विदेश नीति की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।"

उन्होंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के तहत किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग वर्जित है। ऐसे में बिना युद्ध की घोषणा और कूटनीतिक प्रक्रिया के दौरान की गई यह कार्रवाई अंत. रराष्ट्रीय कानून की भावना के विपरीत मानी जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता एक पहले से ही नाजुक क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा, "करोड़ों लोग, जिनमें लगभग एक करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, अनिश्चितता और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।"

राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा चिंताएँ वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और गहरा करते हैं। उन्होंने अमेरिका–इज़राइल के ईरान पर हमलों और ईरान द्वारा अन्य मध्य–पूर्वी देशों पर किए गए हमलों की निंदा की।

सरकार का काम केवल स्कूल खोलना नहीं, बल्कि सुविधाएं भी देना : सीएम

नई दिल्ली (सं)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने को उत्तर–पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन के लिए भूमि पूजन और अस्थायी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह करावल नगर और पूरे उत्तर–पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है। लंबे समय से बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की कमी झेल रहे इलाके के बच्चों को अब अपने ही क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल स्कूल खोलना नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना भी है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार में शिक्षा, सड़क, पेयजल, सीवर और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली है। करावल नगर क्षेत्र में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वर्षों तक यहां के विद्यार्थियों को 4–5 किलोमीटर दूर तक पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। नए केंद्रीय विद्यालय से प्रवेश का दबाव कम होगा और बच्चों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यमुनापार में विकास कार्यों को नई गति मिली है। यमुनापार विकास बोर्ड के पुनर्गठन के बाद करोड़ों रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं।

संदीप दीक्षित ने (आप) के कट्टर ईमानदार होली समारोह पर निशाना साधा

नई दिल्ली (सं)। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के कट्टर ईमानदार होली समारोह पर निशाना साधते हुए कहा कि त्योहार और राजनीति अलग–अलग रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक नेताओं के बस में होता, तो वे हर चीज से खुद को जोड़ना चाहते, यहां तक कि किसी के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी पर भी अपना नाम लिखवा लेते। संदीप दीक्षित ने एएनआई से कहा कि होली और राजनीति अलग–अलग चीजें हैं, और मैं यह बात सबको बताता हूं। जिस तरह कुछ लोग त्योहारों और राजनीति को मिलाने की कोशिश करते हैं, वह बहुत अजीब लगता है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां नेता और राजनीति हर चीज में दखल देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर उनके बस में होता, तो वे किसी के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी पर भी अपना नाम लिखवाना चाहते।

दीक्षित की यह टिप्पणी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर कट्टर ईमानदार होली मनाने के बाद आई है। केजरीवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने सिसोदिया के आवास पर पार्टी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। उन्होंने आगे कहा कि ष्षड्यंत्रों और झूठष् के बावजूद, ईमानदारी और जनता के भरोसे के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता के कारण पार्टी का जोश बरकरार है।

फेसबुक पोस्ट में लिखा गया कि आज मनीष जी के घर पर हमने सभी पार्टी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के साथ श्कट्टर ईमानदारश होली मनाई। उनके षड्यंत्रों और झूठ के बीच भी आम आदमी पार्टी के रंग फीके नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमारी ताकत ईमानदारी और जनता का भरोसा है। हम सत्य और संघर्ष के रंगों के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। यह घटना दिल्ली सरकार द्वारा इस वर्ष होली को शराबबंदी दिवस सूची से हटाए जाने के बाद हुई है। जनवरी में जारी अधिसूचना में कहा गया था कि गणतंत्र दिवस, महाशिव. रात्रि, ईद–उल–फितर, राम नवमी और महावीर जयंती को शराबबंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सऊदी पर मिसाइलें बरसा रहा ईरान, पाकिस्तानी सेना ने क्यों साधी चुप्पी ?

❐ पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरब से बहद अहम रक्षा समझौता किया है। सितंबर में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं और सैन्य नेतृत्व ने समझौते का ऐलान किया था। नाटो स्टाइल के इस समझौते में किसी एक देश पर अटैक को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।

इस्लामाबाद (एजेंसी): सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है। अरामको ने बताया है कि उसकी रास तनुरा तेल रिफाइनरी को ड्रोन हमले के बाद अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है। यह सऊदी अरब के रिफाइनिंग हब में से एक है। इस पर हमला पूरे इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमले का जवाब देते हुए जिन देशों को निशाना बनाया है, उनमें सऊदी अरब भी है। सऊदी पर हमले से पाकिस्तान की तरफ ध्यान गया है क्योंकि दोनों देशों ने बीते साल रक्षा समझौता किया है।

पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरब से बहद अहम रक्षा समझौता किया है। सितंबर में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं और सैन्य नेतृत्व ने समझौते का ऐलान किया था। नाटो स्टाइल के इस समझौते में किसी एक देश पर अटैक को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। वहीं सऊदी अरब और ईरान के घटनाक्रम पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है।

पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होने के बावजूद उसने मिलिट्री एक्शन के बजाय एकजुटता को प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान ने ईरान का हालिया घटनाक्रम पर बहुत संतुलित बयानबाजी की है। इसकी एक अहम वजह उसके पड़ोसी देश ईरान के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और डिप्लोमैटिक रिश्ते हैं।

इस्लामाबाद और तेहरान का हाई–लेवल विजिट और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग सहित द्विपक्षीय जुड़ाव है। ईरान ने पिछले क्षेत्रीय संकटों के दौरान पाकिस्तान के समर्थन की सार्वजनिक रूप से तारीफ की है, जो पारंपरिक रूप से दोस्ताना रिश्तों को दिखाता है। सऊदी से उसका संबंध बहुत पुराना है तो अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते हालिया महीनों में काफी बेहतर हुए हैं।

ईरान के साथ हॉट वॉर में जाना इस्लामाबाद के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि दोनों एक लंबा अस्थिर बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसी कोई लड़ाई पाकिस्तान की अपनी आबादी के अंदर अंदरूनी सेक्टेरियन फाल्ट लाइन को भड़का सकती है। अमेरिका–इजरायल के ईरान पर हमले के खिलाफ कराची और लाहौर जैसे पाकिस्तानी शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं।

पाकिस्तानी जनता ने सड़कों पर आकर ईरान पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया है और अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाया है। यह दिखाता है कि ईरान के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए कितना मुश्किल हो गया है। ऐसा कदम उनको अपने ही लोगों के बीच में अलो. कप्रिय कर सकता है।

एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ समझौता फॉर्मल है। इसे ऑटोमैटिक मिलिट्री बढ़ोतरी की बिना शर्त गारंटी के बजाय एकजुटता का पॉलिटिकल सिग्नल माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान इस समझौते को बनाए रखते हुए युद्ध में सीधी दखल से दूर रहेगा।इसके अलावा पाकिस्तान फिलहाल अपने नॉर्थ–वेस्ट बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ तकरीबन युद्ध जैसी स्थिति में है। भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनापूर्ण रह हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सेना किसी भी सूरत में ईरान के साथ एक नया फ्रंट खोलने की तरफ नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने कोई आक्रामक बयान देने की बजाय शांति की अपील की है। इस्लामाबाद यूएन में चीन और रूस के साथ एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें लड़ाई में कोई पक्ष लेने के बजाय तुरंत और बिना शर्त सीजफायर की मांग की गई है। साफ है कि पाकिस्तान हाई–स्टेक बैलेंसिंग एक्ट पर बढ़ रहा है।

सीएम योगी ने पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को सराहा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को होली के अवसर पर बने खुशनुमा माहौल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जब दुनिया में उथल–पुथल मची है, तब भी यह त्योहार आनंद और उत्साह लेकर आ रहा है।

भगवान नरसिम्हा शोभा यात्रा को संबो. धित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत के मजबूत नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा, हम भारत में होली का यह त्योहार ऐसे समय में मना रहे हैं जब पूरी दुनिया में उथल–पुथल, अशांति और अराजकता का माहौल है। लेकिन भारत, अपने (प्रधानमंत्री मोदी के) महान नेतृत्व में, इस त्योहार को आनंद और उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां न तो भय है, न अराजकता और न ही अविश्वास।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सत्यमेव जयते की भावना से प्रेरित है और आगे कहा कि यदि कहीं भी भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो हमें उसे जला देना चाहिए, और यदि अराजकता, आतंकवाद या उग्रवाद अपना सिर उठाने का घिनौना प्रयास करता है, तो हमें उसे भी नष्ट कर देना चाहिए। होली का उत्सव हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है। इसके अगले दिन होली का सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव मनाया जाता है, जब लोग रंगों से खेलकर आनंद और एकजुटता में लीन हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठनष बताते हुए उसकी प्रशंसा की और घोषणा की कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जुलूस निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, के लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक हैं जिन्होंने इसके संरक्षण में हिंदुओं के सम्मान, गौरव और महिमा, भारत के सनातन धर्म की परंपराओं और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है।

आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे भगवान नरसिम्हा शोभा यात्रा में भाग लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं; समाज का हर वर्ग उनमें भाग ले रहा है, लेकिन कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं है।

5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 2

संपादकीय

ईरान-इजरायल युद्ध से सोना-चांदी ही नहीं मंहगाई भी बेकाबू होगी?

पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव केवल भू–राजनीतिक संकट नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। युद्ध या युद्ध जैसी

संपादक
सलीम अहमद

स्थिति की आशंका ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसका सीधा असर सोना और चांदी जैसी सुरक्षित निवेश धातुओं की कीमतों पर दिखाई दे रहा है जो लगातार उछाल पर हैं। ऐसे में युद्ध अधिक दिनों तक जारी रहेगा तो इससे सोना चांदी के भाव से आसमान छुयेंगे ही, साथ ही साथ मंहगाई भी चरम सीमा पर पहुंचेगी क्योंकि कच्चे तेल के भाव बढने से मंहगाई स्वयं अपना आकार ले लेती है। वैसे भी इन दिनों अमेरिका ने टैरिफ बम से भी अर्थव्यस्था में मंदी ला रखी है जबकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी बेअसर दिखाई दे रहे हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा कर दी है। सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है जो लगातार नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही हैं।

इतिहास गवाह रहा है कि जब –जब दुनिया में युद्ध हुआ है तब–तब आर्थिक संकट गहराता है, निवेशक शेयर बाजार से दूरी बनाकर सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। सोना और चांदी को पारंपरिक रूप से सेफ हेवन माना जाता है। ईरान– इजरायल संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने, वैश्विक व्यापार प्रभावित होने और महंगाई बढने की आशंका ने निवेशकों को कीमती धातुओं की ओर मोड़ दिया है। ज्ञात रहे कि पश्चिम एशिया दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक रही है। यदि युद्ध संघर्ष बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल तय है। तेल महंगा होगा तो परिवहन, उत्पादन और उपभोग की लागत बढ़ेगी, जिससे महंगाई तेज हो सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर सतर्क रुख अपनाते हैं और बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। इस अस्थिरता का लाभ सोना–चांदी को मिलता है।

अगर ऐसे में युद्ध के मद्देनजर भारत की बात करे तो इसका भारत पर व्यापक असर पड़ सकता है। भारत जैसे देश, जो सोने के बड़े उपभोक्ता में से एक हैं, वहां घरेलू बाजार में कीमतों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। शादी–ब्याह का मौसम हो या निवेश का दौरकृसोने की बढ़ती कीमतें लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। चांदी भी औद्योगिक उपयोग में व्यापक है, इसलिए उसकी कीमतों में उछाल उद्योगों की लागत बढ़ा सकता है।

अक्सर देखा गया है कि युद्ध संबंधी खबरों के बीच कीमतें तेजी से चढ़ती हैं, लेकिन हालात सामान्य होते ही कुछ हद तक स्थिरता लौट आती है। इसलिए निवेशकों को भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए। दीर्घकालिक निवेश रणनीति और संतुलित पोर्टफोलियो ही समझदारी भरा कदम है।

ईरान– इजरायल तनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वैश्विक राजनीति का सीधा प्रभाव आम आदमी की थाली और तिजोरी दोनों पर पड़ता है। सोना–चांदी की कीमतों में उछाल केवल बाजार की हलचल नहीं बल्कि विश्व व्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता का संकेत है। ऐसे समय में सरकारों को कूटनीतिक समाधान की दिशा में सक्रिय होना चाहिए और निवेशकों को संयम और विवेक से काम लेना चाहिए। बातचीत से हल निकालना चाहिए। इसके लिए शांति पहल देशों को आगे आना चाहिए ताकि आगामी नर संहार को रोका जा सकें।

अयोध्या अब धार्मिक नगरी ही नहीं अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र है

जानकारों का कहना है कि टेंपल इकोनॉमी का मतलब उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जो मंदिरों के कारण पैदा होती हैं जैसे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु, तीर्थ पर्यटन, मंदिर प्रबंधन, प्रसाद, फूल-माला, होटल, परिवहन और अन्य सेवाएँ। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं रहे बल्कि हजारों सालों से आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र भी रहे हैं। पुराने समय में जब अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर पर चलती थी, तब मंदिर आसपास के लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर देते थे। तीर्थयात्रा के कारण दुकानदारों, कारीगरों, पुजारियों, गाइडों और अन्य काम करने वालों को काम मिलता था। वाराणसी, मदुरै, पुष्कर और उज्जैन जैसे शहर इसके उदाहरण हैं। ये शहर किसी बड़े उद्योग के लिए नहीं बल्कि अपने प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए जाने जाते हैं। मंदिरों के आसपास बनी यह अर्थव्यवस्था सदियों से इन शहरों को सहारा देती रही है।

अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रखी थी और 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हो गया था। इस ऐतिहासिक घटना से भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना तो हुई ही, साथ ही साथ अयोध्या केवल एक धार्मिक नगरी से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में भी उभरकर सामने आने लगी है। केंद्र और यूपी सरकार की कोशिशों से अयोध्या विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रही है।

भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं रहे बल्कि उन्होंने सदियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तिरुपति, वैष्णो देवी और उज्जैन के महाकाल जैसे तीर्थस्थल इसके उदाहरण हैं। अब अयोध्या भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के संगम का नया मॉडल बनती जा रही है। भारत की टेंपल इकोनॉमी को लेकर जानकारों का कहना है कि टेंपल इकोनॉमी का मतलब उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जो मंदिरों के कारण पैदा होती हैं जैसे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु, तीर्थ पर्यटन, मंदिर प्रबंधन, प्रसाद, फूल–माला, होटल, परिवहन और अन्य सेवाएँ। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं रहे बल्कि हजारों सालों से आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र भी रहे हैं।

पुराने समय में जब अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर पर चलती थी, तब मंदिर आसपास के लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर देते थे। तीर्थयात्रा के कारण दुकानदारों, कारीगरों, पुजारियों, गाइडों और अन्य काम करने वालों को काम मिलता था। वाराणसी, मदुरै, पुष्कर और उज्जैन जैसे शहर इसके उदाहरण हैं। ये शहर किसी बड़े उद्योग के लिए नहीं बल्कि अपने प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए जाने जाते हैं। मंदिरों के आसपास बनी यह अर्थव्यवस्था सदियों से इन शहरों को सहारा देती रही है। स्टेटबैंक ऑफ इंडिया और अन्य आर्थिक विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, भारत की टेंपल इकोनॉमी हर साल लगभग 3.02 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ तक का योगदान देती है। यह देश के कुल जीडीपी का करीब 2.3 प्रतिशत से 3 प्रतिशत हिस्सा है। इसी संदर्भ में राम मंदिर अयोध्या की अर्थव्यवस्था

में अहम भूमिका निभा रहा है और शहर को दुनिया के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल कर रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच लगभग 400 करोड़ कर के रूप में सरकार को दिए। इसमें 270 करोड़ जीएसटी और 130 करोड़ अन्य करों के रूप में शामिल हैं। राम मंदिर के निर्माण पर सरकार को लगभग 400 करोड़ जीएसटी मिलने का अनुमान बताय जा रहा है।

अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। धार्मिक पर्यटन ने यहाँ परिवहन, होटल, भोजन, व्यापार और दान अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति दी है। आईआईएम लखनऊ की रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से दिसंबर तक 2024 के बीच अयोध्या में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुँचे। इसी प्रकार 2025 में जनवरी से जून तक 23 करोड़ 81 लाख 64 करोड़ 744 भारतीय और 49993 विदेशी श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए आये।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक शोध के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में सिर्फ अयोध्या से जुड़ी तीर्थ यात्रा और उससे संबंधित गति. विधियों से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का आर्थिक उत्पादन (इकोनॉमिक आउटपुट) होने का अनुमान बताया था। यानी राम मंदिर के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से पर्यटक, होटल, दुकानों और परिवहन जैसी सेवाओं से बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है। जानकारों के अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 3 करोड़ से ज्यादा की भेंट चढ़ाई गई थी। यह दिखाता है कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ–साथ यहाँ बड़ी आर्थिक गतिविधि भी जुड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार को अतिरिक्त 25,000 करोड़ तक का कर राजस्व मिलने की संभावना जताई गई है। इसमें जीएसटी और अन्य तरह के टैक्स शामिल हैं। यानी मंदिर और पर्यटन से राज्य की आमदनी भी बढ़ रही है, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर निर्माण की परियोजना से सीधे 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। यानी मंदिर के प्रबंधन, सुरक्षा, प्रशासन और अन्य कार्यों में हजार से ज्यादा लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं। निर्माण के दौरान स्थिति और भी व्यापक थी। मंदिर के निर्माण कार्यों में 50,000 से अधिक मजदूर अलग–अलग चरणों में जुड़े।

इसमें राजमिस्त्री, इंजीनियर, पत्थर तराशने वाले कारीगर, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग और अन्य श्रमिक शामिल थे। इससे हजारों परिवारों की आमदनी बढ़ी।

जानकारी के अनुसार मंदिर बनने के बाद सिर्फ प्रत्यक्ष रोजगार ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार भी तेजी से बढ़ा। सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से करीब 1.2 लाख नई नौकरियाँ पैदा हुई हैं। ये नौकरियाँ होटल और पर्यटन, हस्तशिल्प और धार्मिक वस्तुओं के व्यापार, स्थानीय परिवहन और टूर गाइड सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बनी हैं। लोगों को कई क्षेत्रों में नया रोजगार या अतिरिक्त कमाई का अवसर मिला।

यूपी सरकार ने अयोध्या को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी बनाने के लिए अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत 85,000 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य सिर्फ मंदिर क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि पूरे शहर को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना है ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।इस योजना में नई सड़कों, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, आधुनिक बस टर्मिनल, पार्किंग जोन और शहरी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। यानी अयोध्या को एक व्यवस्थित और साफ–सुथारे शहर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को भी विक. सित किया गया है।

दिसंबर 2023 से शुरू हुआ महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लेकर आया है। वित्त वर्ष 2025 में इस हवाई अड्डे ने 1.1 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला जो पिछले वर्षों की तुलना में 423 प्रतिशत वृद्धि दिखाता है। इसका मतलब है कि अब देश–विदेश से बड़ी संख्या में लोग सीधे अयोध्या पहुँच पा रहे हैं। भविष्य में इसकी क्षमता को 10 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है।

साथ ही, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। स्टेशन को भव्य डिजाइन, बेहतर वेटिंग रूम, एस्केलेटर, लिफ्ट और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा, नए एक्सप्रेसवे और चौड़ी सड़कों ने अयोध्या को लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर से जोड़ दिया है। इससे यात्रा समय कम हुआ है और व्यापार तथा लॉजिस्टिक्स गतिविधियाँ भी तेज हुई हैं।

अयोध्या के विकास का असर अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है बल्कि आसपास के जिलों तक भी साफ दिखाई दे रहा है। फैजाबाद, बस्ती, सुलतानपुर, अमेठी, लखनऊ और गोरखपुर में भी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। इन क्षेत्रों में होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की संख्या बढ़ रही है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स हब और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है।

इन आर्थिक गतिविधियों से साफ है कि मोदी और योगी सरकार की मंशा केवल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने की नहीं है बल्कि दोनों सरकारें अयोध्या को एक बड़े विजन के तहत विकसित कर रही हैं। जब दुनिया के मानचित्र पर बड़े तीर्थस्थलों का जिक्र किया जाएगा तो उसमें के राम मन्दिर का भी जिक्र अवश्य होगा।

एनसीईआरटी किताबें राजनीति से कब दूर होंगी ?

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक शैक्षिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देना था। स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना; मॉडल पाठ्य पुस्तकों, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को तैयार और प्रकाशित करना तथा शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री आदि का निर्माण करना, शिक्षकों के सेवा–पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना आदि इसकी संघटक इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य हैं लेकिन यह राजनीति से कब दूर होंगी।हाल ही में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में श्न्यायपालिका में

सवाल यह है कि क्या विद्यार्थियों को न्यायपालि. का की कमियों और चुनौतियों से अवगत कराना चाहिए, या ऐसी सामग्री संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है? यह बहस केवल एक अध्याय या पैराग्राफ तक सीमित नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता, शिक्षा की स्वतंत्रा और संस्थागत जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ी है। भारत का लोकतंत्र तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर टिका है। इनमें न्यायपालिका को अंतिम संरक्षक माना जाता है। ऐसे में यदि पाठ्यपुस्तकों में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार की आशंका या उदाहरणों का उल्लेख होता है तो कुछ लोगों को यह संस्थान की छवि पर आघात जैसा लगता है। लेकिन दूसरी ओर, लोकतंत्र का मूल तत्व ही यह है कि किसी भी संस्था को आलोचना और समीक्षा से परे नहीं रखा जा सकता।

भ्रष्टाचार से जुड़े अंश को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है हालांकि यह विवाद नया नहीं है वरन पुरानी बोतल में नई शराब है। सवाल यह है कि क्या विद्यार्थियों को न्यायपालिका की कमियों और चुनौतियों से अवगत कराना चाहिए, या ऐसी सामग्री संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है? यह बहस केवल एक अध्याय या पैराग्राफ तक सीमित नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता, शिक्षा की स्वतंत्रता और संस्थागत जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ी है।भारत का लोकतंत्र तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर टिका है। इनमें न्यायपालिका को अंतिम संरक्षक माना जाता है।

ऐसे में यदि पाठ्यपुस्तकों में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार की आशंका या उदाहरणों का उल्लेख होता है तो कुछ लोगों को यह संस्थान की छवि पर आघात जैसा लगता है। लेकिन दूसरी ओर, लोकतंत्र का मूल तत्व ही यह है कि किसी भी संस्था को आलोचना और समीक्षा से परे नहीं रखा जा सकता।

शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थाओं का महिमामंडन करना नहीं बल्कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना भी है। यदि इतिहास, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र की किताबों में केवल आदर्श चित्र ही दिखाया जाए और वास्तविक चुनौतियों पर पर्दा डाल दिया जाए, तो विद्यार्थी अधूरी समझ के साथ बड़े होंगे। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप कोई कल्पना नहीं, बल्कि समय–समय पर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। पारदर्शिता और आत्ममंथन से ही संस्थाएं मजबूत होती हैं।

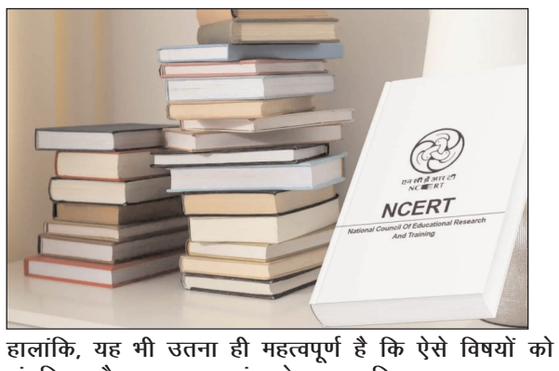

हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे विषयों को संतुलित और तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। सनसनीखेज भाषा या एकतरफा दृष्टिकोण से छात्रों के मन में अविश्वास का भाव पैदा हो सकता है। इसलिए पाठ्यपुस्तकों में यदि श्न्यायपालिका में भ्रष्टाचारश जैसे विषय शामिल हों, तो उनके साथ सुधारात्मक कदमों, न्यायिक जवाबदेही की व्यवस्थाओं और संस्थागत सुधारों का भी उल्लेख होना चाहिए।

इस विवाद के पीछे व्यापक प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को इतना परिपक्व मानते हैं कि वे आलोचना सह सकें? यदि हां, तो पाठ्यपुस्तकों में चुनौतियों का उल्लेख लोकतंत्र की मजबूती का संकेत होना चाहिए, न कि कमजोरी का।

अंततरू, समाधान संतुलन में है–न तो संस्थाओं की अंधभक्ति और न ही अनावश्यक अविश्वास। शिक्षा का दायित्व है सच को तथ्यात्मक, जिम्मेदार और संतुलित रूप में प्रस्तुत करना। तभी आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र को समझेगी, प्रश्न पूछेगी और उसे बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी। वहीं की पाठ्यपुस्तकों से श्न्यायपालिका में भ्रष्टाचारश संबंधी कुछ अंशों को हटाने या संशोधित करने को लेकर बहस तेज हो गई है। शिक्षा जगत, राजनी. तिक दलों और अभिभावकों के बीच यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या छात्रों को संस्थाओं की कमजोरियों से अवगत कराना चाहिए या केवल आदर्श तस्वीर ही प्रस्तुत की जानी चाहिए?

पाठ्यपुस्तकें केवल जानकारी का माध्यम नहीं बल्कि सोचने की दिशा भी तय करती हैं। अगर किसी पुस्तक में न्यायपालिका की भूमिका, उसकी स्वतंत्रता और उसके सामने आने वाली चुनौतियोंकृजैसे भ्रष्टाचारकृका उल्लेख होता है, तो वह विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं की जटिलता समझने में मदद करता है।

भारत जैसे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट इंडिया और उच्च न्यायालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं की गरिमा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, लेकिन उनकी आलोचना या समस्याओं पर विमर्श भी लोकतंत्र का हिस्सा है। किसी भी संस्था में भ्रष्टाचार का उल्लेख करना उस संस्था को बदनाम करना नहीं बल्कि सुधार की संभावना को स्वीकार करना है। यदि पाठ्यक्रम से ऐसे संदर्भ हटा दिए जाते हैं, तो छात्रों के सामने अधूरा चित्र प्रस्तुत होता है। हालांकि यह भी सच है कि भाषा संतुलित और प्रमाण आधारित होनी चाहिए। किसी सामान्यीकरण या अति. रंजना से बचना आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों में संस्थाओं के प्रति अविश्वास न पनपे। लो. कतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे बड़ी ताकत होती है। न्यायपालिका स्वयं भी समय–समय पर आत्ममंथन और सुधार की आवश्यकता स्वीकार करती रही है। ऐसे में शिक्षा से यथार्थ के अंश हटाना क्या लोकतांत्रिक परिपक्वता के अनुरूप है? विद्यार्थियों को यह समझाना अधिक उपयोगी होगा किकृ न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसमें सुधार की व्यवस्था मौजूद है,और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच व दंड की प्रक्रिया भी है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सहित वर्तमान सत्ता ने ध्यान दिया है लेकिन आज मुद्दा बन गया है।

सारा सच

साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र
– मुख्य सम्पादक –
सलीम अहमद
– सह संपादक –
फहमीना सिद्दीकी,
शमीम अहमद
– सलाहकार–
डा. फरीद चुगतई
(INN Today)
शबनम खान (मानवाधिकार कार्यकता), डा. जावेद फारूकी (सामाजिक कार्यकर्ता), दीपक त्यागी (एडवोकेट), मोहम्मद मो. हसिन, के.के. गौतम (एडवोकेट), प्रदीप महाजन (आईएनएस), राजकुमार गुप्ता (सामाजिक कार्यकर्ता), संजय दुबे (कल्पना फाउंडेशन)
–छायाकार–
साजिद अली, सुधीर कुमार
ब्यूरो/विज्ञापन प्रतिनिधि
– दिल्ली –
रविन्दर कुमार, विशाल चौहान
जयपुर (राजस्थान)
– रिंकू
चंडीगढ़ – हरियाणा
– बलराम शर्मा
शिमला (हिमाचल प्रदेश)
– शान मोहम्मद
आगरा (उत्तर प्रदेश)
– हसीब हुसैन
अलीगढ (उत्तर प्रदेश)
– मो. फारूख
फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश)
– फैसल मसरूर
मुज्जफरनगर (उत्तर प्रदेश)
– मो. इलियास

Chetan Srivastava
98100 63006, 93100 63006
kaagzaat
कागज़ात
a complete property Documentation point
DELHI DOCUMENTATION CENTRE
Specialists in : Drafting & Registration of documents for Free Hold, Lease Hold, Commercial, Industrial, DDA, L&DO Society Properties & Flats wih Computer Processing & Manual Typing
LEASE HOLD TO FREE HOLD A SPECIALITY
Off : UG-28 Suneja Tower-I
Distt. Centre Janak Puri, New Delhi-58
Ph : 2554 1618, 2561 7461
Br. Off :- Shop No.2 S-2/100
Old Mahavir Nagar, Near
Mangla Hospital, New Delhi-18

5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 3

'दिल्ली लखपति बेटी योजना' की हुई शुरुआत

❒ सीएम बोलीं- ग्रेजुएशन पर मिलेंगे सवा लाख रुपये

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं और लड़कियों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना, श्दिल्ली लखपति बेटी योजनाश की शुरुआत की घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मुफ्त सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है और राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को पिंक कार्ड भी प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के सभी निवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूं। हमने मुफ्त सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है और दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड भी प्रदान किए हैं।

अब हमारी दिल्ली की बहनें दिल्ली की डीटीसी बसों में यात्रा कर सकेंगी। आज हमने दिल्ली की बेटियों के लिए एक नई योजना, दिल्ली लखपति बेटी योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली सरकार बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक होने तक सहायता प्रदान करेगी। स्नातक होने वाली प्रत्येक लड़की के खाते में 61,000 रुपये जमा किए जाएंगे। परिपक्वता पर, उसे लगभग 1.25 लाख रुपये मिलेंगे। अब दिल्ली की बेटियां लखपति बनेंगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि श्लखपति बेटी योजनाश का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में लड़कियों

को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इससे पहले दिन में, गुप्ता ने सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण महिला–केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया, जिनमें राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना और दिल्ली लखपति बेटी योजना शामिल हैं।

शिक्षा, गतिशीलता और घरेलू सशक्तिकरण पर जोर देते हुए, उन्होंने घोषणा की कि लाडली–लाडली योजना के तहत 30,000 लड़कियों के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से वितरित कर दी गई है

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ष्यह जीवन के तीन पहलुओं – शिक्षा, गतिशीलता और घरेलू सशक्तिकरण – को छूने का प्रयास है। मैं दिल्ली की बेटियों को बधाई देती हूं। जब सरकार ने जांच की, तो हमने पाया कि 1.75 लाख लड़कियों के लिए लाडली–लाडली योजना के लिए निर्धारित धनराशि सरकारी खातों में पड़ी हुई थी। इसलिए, पहले चरण में, हमने 30,000 लड़कियों का पता लगाया और डीबीटी के माध्यम से 90 करोड़ रुपये दिए गए।ष

अधिकारियों के अनुसार, ये चार योजनाएं श्सहेली पिंक स्मार्ट कार्डश, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पुंजी मेरा अधिकार हैं। इस पहल के तहत, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड को राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) ढांचे के अंतर्गत पेश किया जाएगा, जिससे पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह कार्ड मेट्रो और क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आर.आई.एस.) में भी सशुल्क यात्रा की सुविधा देगा, जिसे एक ही टच–फ्री स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया जा सकेगा।

कार्ड लगभग 50 डीएम/एसडीएम कार्यालयों और चयनित डीटीसी केंद्रों पर जारी किए जाएंगे, जहां पात्रता का सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा और लाभार्थी के मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा।

ग्रीन टैक्स वसूली पर नितिन गडकरी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों (कमर्शियल व्हीकल्स) से वसूले जा रहे पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (एनवायरनमेंट कम्पनसेशन चार्ज) (म्ब्ब्) को लेकर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर यह शुल्क पर्यावरण सुधार के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो फिर इसे वसूला ही क्यों जा रहा है। ECC (ईसीसी) की शुरुआत 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रवेश करने वाले प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर वायु प्रदूषण को कम करना। सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना था। यह शुल्क नियमित टोल टैक्स के अलावा वसूला जाता है।

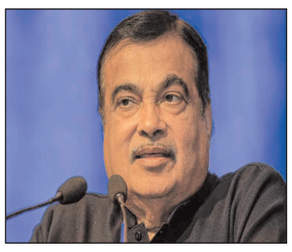

दिल्ली में एक कार्यक्रम में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ हुई एक बैठक में सीधे सवाल किया, आप ग्रीन एक्टिविटीज के लिए क्या योगदान दे रहे हैं? जवाब मिला– कोई योगदान नहीं।

इसके बाद उन्होंने पूछा, अगर कोई पर्यावरणीय काम नहीं हो रहा, तो यह टोल क्यों वसूला जा रहा है? गडकरी ने कहा कि एमसीडी ने उन्हें बताया कि यह ग्रीन टैक्स निगम के लिए आर्थिक रूप से अहम है। इस पर उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार एमसीडी को 800–900 करोड़ रुपये की ग्रांट दे सकती है, ताकि आम लोगों पर यह अतिरिक्त बोझ न डाला जाए और ईसीसी को खत्म किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस शुल्क को तुरंत बंद करने का अनुरोध किया है।

गडकरी के अनुसार, अधिकारियों ने ईसीसी जारी रखने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया।

इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आग्रह किया है किअदालत से दोबारा इस फैसले पर विचार कराया जाए, ताकि इस टैक्स से परेशान लोगों को राहत मिल सके। गडकरी ने बताया कि जब उनके मंत्रालय ने ईसीसी से जुटाए गए फंड की जांच की, तो पाया गया कि यह पैसा वायु गुणवत्ता सुधारने के मूल उद्देश्य में इस्तेमाल नहीं किया गया।यही वजह है कि उन्होंने इस टैक्स की प्रासंगिकता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं।

दिल्ली में डेंगू के 39, मलेरिया के आठ और चिकनगुनिया का एक मामला आया सामने

नई दिल्ली (एजेंसी)। एमसीडी के जनस्वास्थ्य विभाग की एंटी मलेरिया ऑपरेशंस इकाई की 28 फरवरी की साप्ताहिक रिपोर्ट में सामाने आया है कि इस साल अब तक दिल्ली में डेंगू के 39, मलेरिया के आठ और चिकनगुनिया का एक

मामला दर्ज हुआ है। हालांकि, तीनों बीमारियों से अब तक कोई मौत नहीं हुई है। 2025 में इसी अवधि में डेंगू के 69 और मलेरिया के आठ मामले सामने आए थे, जबकि 2024 में डेंगू के 81 और मलेरिया के 15 मामलों दर्ज हुए थे।जोनवार आंकड़ों के अनुसार, मलेरिया के आठ मामलों में से पांच वेस्ट जोन में आए है, जबकि एक–एक मामला सेंट्रल और सिटी एसपी जोन में दर्ज हुआ। डेंगू के 39 मामलों में वेस्ट जोन में छह, सेंट्रल में पांच, सिविल लाइंस में तीन और नजफगढ़ में तीन मामले सामने आए, जबकि अन्य जोनों में छिटपुट केस दर्ज हुए।

एमसीडी ने एक जनवरी से 28 फरवरी के बीच मच्छर प्रजनन रोकथाम के लिए निरीक्षण के दौरान 2,179 घरों में लार्वा पमिला और 4,443 घरों में स्प्रे कराया था। लापरवाही बरतने पर 2,669 कानूनी नोटिस जारी किए गए और 254 अभियोजन दायर किए गए। इसके अलावा 16,200 स्थानों पर गैंबूसिया मछलियां छोड़ी गईं, जो मच्छरों के लार्वा को नष्ट करती हैं।

'आप' को खत्म करने की साजिश रची गई : भगवंत सिंह मान

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक रैली आयोजित की गई।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब वह देश के सामने बेनकाब हो चुकी है।

मान ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब विरोधी है, जिसने आरडीएफ और जीएसटी समेत पंजाबियों के करोड़ों रुपये रोक रखे हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी देश से नफरत और झूठ की राजनीति खत्म करने आई है और इस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मान ने कहा कि जब भी पार्टी पर मुस. ीबत आती है, वह दोगुनी ताकत से उभरती है। अरविंद केजरीवाल ने अन्य दलों को घोषणापत्र में स्कूल, अस्पताल, बिजली और रोजगार की बात लिखने पर मजबूर किया है। उन्होंने अरविंद

केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया।

मान ने आगे बताया कि केजरीवाल ने जेल से भी पंजाब के लोगों की चिंता की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जालंधर उपचुनाव में पार्टी की जीत का भी जिक्र किया, जब शीर्ष नेतृत्व जेल में था और पार्टी ने बैकअप टीम से काम चलाया। मान ने शहीद भगत सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और आम आदमी पार्टी अब और बड़ी होकर निकलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश की गद्दी पर बैठे किरायेदार बताया, यह देश किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में 90 फीसदी कुर्बानियां पंजाबियों ने दीं, फिर भी केंद्र सरकार पंजाब का 8000 करोड़ रुपये का आरडीएफ और जीएसटी का पैसा रोक लेती है। पंजाब में आई ऐतिहासिक बाढ़ के लिए मात्र 1600 करोड़ रुपये की घोषणा की गई, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं दिए गए। उन्होंने भाजपा को पंजाब विरोधी और आम आदमी पार्टी विरोधी बताया। भगवंत मान ने देश की सीमाओं की सुरक्षा, हरित क्रांति और आजादी में पंजाबियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी का पौधा लगा था, तब भी सबसे पहले चार सांसद पंजाबियों ने ही दिए थे। मान ने विश्वास दिलाया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर तोहफा देगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी टीम के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा।

राजधानी में महंगी होगी शराब

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में नए वित्तीय वर्ष से शराब महंगी हो सकती है। 2026–27 की एक्साइज अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में 10 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट समेत कई श्रेणी के लाइसेंस पर लागू होगी।

दिल्ली सरकार के आबकारी, मनोरंजन एवं लक्जरी टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की लाइसेंस अवधि के लिए फीस बढ़ाने का आदेश जारी किया है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद एल–28/एल–28एफ और एल–29/एल–29एफ श्रेणी के लाइसेंसों के नवीनीकरण को हरी झंडी दी गई है।नई व्यवस्था के तहत भारतीय और विदेशी शराब पर लगने वाली वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 फीसदी इजाफा किया गया है। माना जा रहा है कि लाइसेंस शुल्क बढ़ने का असर बाजार में शराब की कीमतों पर भी पड़ सकता है।सभी लाइसेंसधारकों को ई–आबकारी पोर्टल पर अपनी एएक्सडी आईडी से ऑनलाइन आवेदन कर नवीनीकरण कराना होगा। विभाग ने भुगतान की समयसीमा भी तय की है। 28 फरवरी तक केवल मूल लाइसेंस शुल्क देना होगा।1 मार्च से 31 मार्च के बीच भुगतान करने पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

Vinod Kumar 9899317267
Varun Kumar 9212738941 9999963395
VARUN Canvas-Company
Wholesaler of : All Kinds of Blankets, Cotton Cloth.
Spl. in : Blankets, Plastic Tirpal, Plastic Tubes, Cotton Cloths, Tents, Car-Scooter Cover
12-A, Azad Market, Near Pul Mithai, Delhi-6
E-mail: varuncanvasco@yahoo.co.in

IPCS
Indian Pest Control Services
PRE & POST CONSTRUCTION ANTI-TERMITE TREATMENT
Dr. P. K. Sahani (Entomologist)
WZ-250 C, NEAR MTNL EXCHANGE OPP. PUSA INSTITUTE INDER PURI, NEW DELHI-110012
PH. 64522051 M. 9810437316
E-mail: pks0573@rediffmail.com
ipcs.7340@rediffmail.com

रोहिणी के आशा किरण में मंत्री ने विशेष बच्चों संग मनाई होली

नई दिल्ली (सं)। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने मंगलवार को रोहिणी स्थित आशा किरण होम में दिव्यांग एवं मानसिक रूप से कमजा. `र विशेष बच्चों के साथ होली मनाई। मंत्री ने बच्चों के साथ रंग खेला, उनका हालचाल जाना और उन्हें मिठाइयां वितरित कीं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की मुस्कान ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि अपनत्व और समावेश का प्रतीक है।

रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने बताया कि वे दिवाली, रक्षाबंधन और अपना जन्मदिन भी ऐसे ही संस्थानों में बच्चों और वृद्धजनों के साथ मनाते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है।

संस्थानों में स्वच्छता, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने उत्तर–पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर में प्रस्तावित स्कूल–कम–होम के लिए आवंटित भूमि के निरीक्षण की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिव्यांग. जनों के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

पिंक कार्ड अनिवार्य करने के फैसले पर आप ने भाजपा पर लगाया आरोप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड अनिवार्य करने के फैसले पर भाजपा सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि निर्णय से पूर्वांचल की गरीब महिलाओं का मुफ्त यात्रा का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली के आधार कार्ड जैसी शर्तें लागू की जा सकती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पूर्वांचल की उन महिलाओं को परेशानी होगी, जिनके पास अपने मूल राज्य का आधार कार्ड है। उन्होंने इसे भाजपा की भेदभावपूर्ण नीति करार दिया है।

सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि पहले की योजना में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं थी। अब कार्ड प्रणाली लागू होने से दलालों और अधिकारियों की भूमिका बढ़ेगी और आम महिलाओं को कागजी औपचारिकताओं के लिए इधर–उधर भटकना पड़ेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि पिंक कार्ड बनाने के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है और किस आधार पर पात्रता तय की जाएगी।

2.0 COMMUNICATION

आखिर कब तक ?

शबनम खान

1. यदि आप शासनिक स्तर पर न्याय चाहते हैं।
2. यदि आपकी पुलिस या अन्य किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
3. यदि कोई सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी काम के बदले आपसे रिश्वत मांग रहा है।
4.यदि कोई आपका शारीरिक एवं मानसिक रूप से शोषण कर रहा है।
5. यदि आप जीवनसाथी या किसी अन्य संबंधी द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं।
6. यदि किसी कार्यरत महिला/पुरुष का कार्यालय में अन्य तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से शोषण हो रहा है।
7. यदि किसी बुजुर्ग को परिवार में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है।
8. यदि किसी शिक्षण संस्थानों में छात्र अथवा छात्राओं का मानसिक या शारीरिक स्तर पर शोषण हो रहा है।
9. यदि कोई आपको बाल मजदूरी के लिए बाध्य कर रहा है।
10. यदि शिक्षण संस्थानों द्वारा आपसे डेवलपमेंट चार्ज या डोनेशन के नाम पर अवैध धन वसूला जा रहा है।
11. यदि उपभोक्ता किसी सेवा या उत्पाद से संतुष्ट नहीं है।
12. यदि सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों में आपकी देख रेख उचित रूप से नहीं हो रही है तो घबराए नहीं, सम्पर्क करें:–

Miss Shabham Khan (President)
(Human Rights Activist)
EK Koshish Aur Abhi (EkAA)
N.G.O.
Dedicated to Human Rights & Social Justice
E-mail :
Khanshabnam.humarightactvist@Yahoo.in
www.ekkoshishaurabhi.org

स्वामी मुद्रक, प्रकाशक व संपादक सलीम अहमद द्वारा M/s Vats Offset, Muddra House, Opp C-Block Barat Ghar Chouda Raghunath Pur Sector 22, Noida Uttar Pradesh से मुद्रित व 12/596, गली नंबर–2, वेस्ट गुरू अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92 से प्रकाशित।
संपादक : सलीम अहमद, सारा सच साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों व समाचारों की सहमति आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

दिल्ली साकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएं कार्यकर्ता : वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्ली (सं)। दिल्ली सरकार का एक कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न लोक सभाओ में प्रवास करते हुए पूर्वी दिल्ली लोकसभा में दस्तक दी और कार्यकर्ताओं व आम लोगों के बीच अपनी सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया ।

इस मौके पर वीरेन्द्र सचदेवा एवं रेखा गुप्ता के साथ क्षेत्रीय सांसद एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, यमुनापार विकास बोर्ड अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली, प्रवास कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र चांदोलिया, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेन्द्र धामा, शाहदरा जिलाध्यक्ष दीपक गाबा, विधायक अभय वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सरदार तरविन्दर सिंह मारवाह, रविन्द्र सिंह नेगी, रविकांत, डॉ अनिल गोयल, संजय गोयल, पंकज लूथरा , भाजपा शाहदरा ज़िला प्रवक्ता भारत गौड़ एवं अन्य जिला पदाधिकारी भी उपस्थिति रहे ।

केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान कार्ड (10 लाख तक मुफ़्त इलाज़) बनाकर रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के बुजुर्गो को प्राणवायु देने का काम किया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा भी उससे अछूता नहीं है।आज दिल्ली में तीन इंजन की सरकार है तो लगातार विकास कार्य हो रहे हैं।

श्री मल्होत्रा ने यह भी बताया कि डीएनडी– फरीदाबाद– सोहना कनेक्टिविटी कॉरिडोर, पंजाबी बागदृटिकरी बॉर्डर कॉरिडोर, महरौली गुरुग्राम कॉरिडोर आदि से ना सिर्फ दिल्ली के जाम खत्म होंगे बल्कि ये सभी दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का माध्यम भी बनेंगे।वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक साल में जितने भी काम किए गए हैं, अब संगठन का दायित्व बनता है सरकार के कार्यों को घर–घर तक पहुंचाये।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हमें लोकसभा के साथ दिल्ली सरकार और निगम तीनों जगह अपना आशीर्वाद दिया है कि इसलिए अब हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वे जनता की समस्याओं को लगातार सुने और उसके समाधान के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि आपकी सरकार निरंतर कार्य कर रही है । सरकार की कार्यशैली का परिणाम है कि अब दिल्ली तेजी के साथ बदल रही है । हर ओर विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है।

Chief Pattern SaraSach

Shabnam Fazil Khan
(Human Right Activist , RTI Activist , Social Reformer, international tv debate panelist)

चुप्पी तोड़ें

यदि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग कर रहा है या कोई भी विभागीय अधिकारी आपका आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण करता है या फिर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है तो कृपया अपनी शिकायत/जानकारी पर हमें लिख भेजें। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपकी इच्छानुसार आपका नाम व पहचान गुप्त रखी जाएगी।

लिखें

मुख्य संपादक : सलीम अहमद
सारा सच
12/596 गली नंबर: 2, वेस्ट गुरू अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
E-mail : sarasach786@gmail.com

5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 4

सारा सच
www.sarasach.com

PRESENT हमारीवाणी
SHOW YOUR TALENT
YOUR PEN YOUR VOICE

दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

◆वर्ष : 8 ◆अंक : 33 ◆वीरवार 5 मार्च से 11 मार्च, 2026 ◆पृष्ठः 8 ◆मूल्यः 3 रुपए, ◆हिजरी 1446 R.N.I. No. DELHIN/2018/76166 sarasach786@gmail.com

प्रस्तुति
रशीद अकेला
(झारखंड)

'वो अकेला मर्द था'

सारे अमेरिका के तलवे चाटने वाले, ग़द्दारी का ज़रूर दर्द था
सारे नामर्दों के बीच मगर वो अकेला मर्द था

बूढ़ा था मगर था वो इकलौता शेर
मज़लूमों का इकलौता हमदर्द था

सब के सब गद्दार इंसानियत के दुश्मन
अमेरिका के आगे नतमस्तक सबका सर था

बूढ़े शेर का शिकार करने आए थे झुंड में नामर्द

शहीद हुआ मगर बता दिया वो इकलौता मर्द था

अमेरिका किसी का सागा नहीं समझोगे एक दिन
याद करोगे इंसानियत को बचाने का एक वक्त था

इंसानियत से भी बड़ा कोई धर्म हो गया क्या ?
शिया सुन्नी भूल लड़ने वाला क्या एक ही मर्द था

भले मिट जाए आज नक्से से ईरान रशीद
जमाना रखेगा याद के वहाँ कोई मर्द था

डा. मोहिनी गुप्ता को 'मातृभाषा रत्न' मानद उपाधि नेपाल में लहराया परचम, बढ़ाया भारत का गौरव

शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (21 फ़रवरी 2026) के पावन अवसर पर मोहिनी गुप्ता को "मातृभाषा रत्न" मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मातृभाषा हिंदी के संरक्षण, संवर्धन एवं साहित्यिक उन्नयन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

फाउंडेशन के अध्यक्ष आनन्द गिरि मायालु ने लुंबिनी–5, नेपाल से जारी प्रशस्ति पत्र में कहा कि मो. हिनी गुप्ता की साहित्य साधना, समर्पण और सृजनशीलता भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रा. `त है। एक साहित्यकार, शिक्षिका और समा. जसेवी के रूप में वे निरंतर हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में सक्रिय हैं।

यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत कृतित्व का गौरव है, बल्कि राजगढ़ (ब्यावरा) और समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए भी गर्व का विषय है। उनकी उपलब्धि से क्षेत्र में साहित्यिक चेतना को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिला है।

मोहिनी गुप्ता राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी कोटा में जन्मी और वर्तमान में राजगढ़ (ब्यावरा) में निवासरत मोहिनी गुप्ता साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभरकर सामने आई हैं। एम.ए., बी.एड. एवं एम.ए. (एजुकेशन) जैसी उच्च शैक्षणिक उपाधियों से संपन्न मोहिनी जी ने शिक्षा के साथ आध्यात्मिक साधना को भी अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया है। वे वर्तमान में श्री फलौदी मेटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल, राजगढ़ की डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रही हैं।

साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हास्य विधा से करने वाली मोहिनी गुप्ता आज कविता, गीत, हाइकु, कहानी, निबंध और संस्मरण सहित अनेक विधाओं में सक्रिय हैं। अल्प शब्दों में गहन भाव व्यक्त करना उनकी लेखनी की विशिष्ट पहचान है। वर्ष 2024 में लखनऊ में "भारत रत्न अटल सम्मान" तथा फरवरी 2026 में इंदौर में "हिंदी रत्न सम्मान" से अलंकृत होना उनकी साहित्य साधना का प्रमाण है। उनका एकल काव्य संग्रह "ओस की एक बूँद" तथा साझा संकलनों में प्रकाशित रचनाएँ पाठकों के हृदय को स्पर्श करती हैं। वे साहित्य को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानती हैं।

आखिर अमेरिकी वर्चस्व की कीमत कब तक चुकाएगी शेष दुनिया?

देखा जाए तो समकालीन दुनिया भी अमेरिकी वर्चस्व की यही स्थिति है जिसकी भारी कीमत शेष चुकाती आई है और आगे भी चुकाती रहेगी. इन कीमतों में सैन्य हस्तक्षेपों से उत्पन्न युद्ध, तरह तरह से आर्थिक शोषण और डालर–प्रधान मौद्रिक व्यवस्था शामिल हैं। वैसे तो अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा बजट और वैश्विक सैन्य अड्डे नेटवर्क अन्य देशों पर हमेशा दबाव बनाए रखते हैं जबकि डालर डिप्लोमेसी और डालर की आरक्षित मुद्रा स्थिति विकासशील देशों को आर्थिक निर्भरता में बांधती है।यही वजह है कि अमेरिकी वर्चस्व की वैश्विक लागत आएदिन बढ़ती जा रही है और उसके नानाविध हथकंडे से दुनियावी देशों को असहमति की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि 'समरथ को नहीं दोष गोसाईं' यानी कि ताकतवर लोगों को कोई भी दैव दोष तक नहीं लगता है. यदि समकालीन लोकतांत्रिक कसौटियों और प्रवृत्तियों में इसे देखें तो देश–दुनिया के सभी वैधानिक नियमन शक्तिशाली देशों और लोगों के ही पक्ष में कार्य करते प्रतीत होते हैं। वाकई उनके किसी भी लोकविरोधी या जनविरोधी कार्य में प्रायः कोई न्यायिक बाधाएं तक नजर नहीं आतीं और न ही उनमें कोई दोष या खामियां तलाशी जाती हैं। आलम यह है कि किसी भी संसद, सर्वोत्तम न्यायालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक में ऐसे मामले पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं किये जाते और अंततः मामले रफादफा करवा दिए जाते हैं। कबीलाई भाषा में कहें तो जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली कहावत न केवल ग्रामीण जगत की मानसि. कता बल्कि आधुनिक नृशंस विश्व के मानस पटल तक पर हावी महसूस होता है। बहरहाल इससे बचने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। सच कहूं तो ष्वीर भोग्या वसुंधराष वाली कहावत प्रायः हर जगह चरितार्थ होती आई है। देखा जाए तो समकालीन दुनिया भी अमेरिकी वर्चस्व की यही स्थिति है जिसकी भारी कीमत शेष चुकाती आई है और आगे भी चुकाती रहेगी. इन कीमतों में सैन्य हस्तक्षेपों से उत्पन्न युद्ध, तरह तरह से आर्थिक शोषण और डॉलर–प्रधान मौद्रिक व्यवस्था शामिल हैं। वैसे तो अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा बजट और वैश्विक सैन्य अड्डे नेटवर्क अन्य देशों पर हमेशा दबाव बनाए रखते हैं जबकि डॉलर डिप्लोमेसी और डॉलर की आरक्षित मुद्रा स्थिति विकासशील देशों को आर्थिक निर्भरता में बांधती है।

यही वजह है कि अमेरिकी वर्चस्व की वैश्विक लागत आएदिन बढ़ती जा रही है और उसके नानाविध हथकंडे से दुनियावी देशों को असहमति की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

पहले की बात छोड़ भी दी जाए तो हाल ही में बेनेज़ुएला की सरकार के बाद ईरान की सरकार का जो हश्र अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कर दिखाया है, वह बिल्कुल ताजा और नया उदाहरण बनकर उभरा है, जहां ईरान को समर्थन देने वाले अंतर्राष्ट्रीय देशों की बेचारगी भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाती है। जी हां, रूस–चीन–उत्तर कोरिया गठजोड़ की जिन्होंने ईरानी तानाशाह खामेनेई को मनबढ़ बनवा कर मरवा दिया और हाथ पर हाथ धरे रहकर तमाशा देखते रहे या विरोध की औपचारिकता भर निभाते रहे।यदि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आपने गौर किया होगा तो स्पष्ट महसूस हुआ होगा कि इराक–अफगानिस्तान जैसे लंबे संघर्षों से अमेरिकी सैन्य अतिभारण बढ़ा जिससे वैश्विक अस्थिरता और आर्थिक बोझ बढ़ा। वहीं, कोई भी देश डॉलर प्रभुत्व से अमेरिकी ऋण आसानी से ले सकता है लेकिन अन्य देशों को महंगाई और व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, पेट्रोडॉलर सिस्टम तेल व्यापार को डॉलर में बांधता है, जो चीन जैसे आयातकों के लिए नुकसानदेह है।

हालांकि, अमेरिकी वर्चस्व में यदाकदा क्षय के संकेत भी मिलते आए हैं लेकिन डॉनल्ड ट्रंफ के कार्यकाल में अमेरिका का जो रक्तरंजित चेहरा खुलकर सामने आया है वह अमेरिका को चुनौती देने की सोच रखने वाले देशों को किसी खुली नसीहत की तरह है। पहले टैरिफ युद्ध और अब खुली जंग ने यह साफ कर दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मार्ग पुनः प्रशस्त हो चुके हैं। इसमें डीप स्टेट की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

वहीं अपने आक्रामक रुख और शातिर कूटनीति से जिस तरह से उन्होंने ब्रिक्स देशों की बखिया उधेड़नी शुरू की है, ऐसा उदाहरण अतीत में 1944 के बाद कभी नहीं मिला है।

यूं तो 2010 की भविष्यवाणी के अनुसार, अमेरिकी प्रभुत्व 2025 तक कमजोर हो सकता था जो आंतरिक विभाजन और प्रतिद्वंद्वियों के उदय से सत्य सिद्ध हो रही है।

लेकिन डॉनल्ड ट्रंप के आक्रामक प्रशासन ने अब स्थिति को अपने पक्ष में बदलने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके लिए अमेरिकियों को ट्रंप को बधाई देनी चाहिए। भले ही 2026 में डॉलर 10ः गिरा, ब्याज दर अंतर कम होने से दबाव बढ़ा, लेकिन अब वह मुनाफे में रहेंगे क्योंकि दुनिया को पुनः अस्थिर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं BRICS (40ः वैश्विक GDP) अब SWIFT विकल्प और राष्ट्रीय मुद्राओं पर जोर दे रहा है लेकिन अमेरिकी आक्रामकता जल्द ही सबकुछ अपने हित के अनुकूल कर लेगी।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुधुरुवीय विश्व उभर रहा है, जहां चीन, रूस, भारत और यूरोपीय संघ जैसे देश शक्ति बांट रहे हैं। इसके बावजूद, इनके आंतरिक और नीतिगत अंतर्विरोधों से अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिकी प्रभुत्व तत्काल समाप्त नहीं होगा, बल्कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां (जैसे न्छ्व, ॅभ् से अलग राह) इसे और तेज कर सकती हैं। लिहाजा शेष दुनिया अमेरिकी हौसलों और दूरदर्शिता भरे लोकतांत्रिक षड्यंत्रों की कीमत चुकाना जारी रखेगी जब तक ठत्प्ै जैसी पहलें मजबूत न हों।

भले ही चीन अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और तकनीकी मोर्चों पर बहुआयामी चुनौती दे रहा है जिससे यह चुनौती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करती है जहां चीन वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। जहां आर्थिक मोर्चा पर चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (ठत्प्) के जरिए 140+ देशों में निवेश बढ़ाया जो अमेरिकी प्रभाव वाले क्षेत्रों में कर्ज जाल और बंदरगाह नियंत्रण बनाता है।

वहीं डॉलर प्रभुत्व को चुनौती देते हुए, चीन ठत्प्ै के माध्यम से डी–डॉलरीकरण को बढ़ावा दे रहा है जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग और नई भुगतान प्रणाली शामिल है। यही वजह है कि 2026 तक चीन की GDP अमेरिका के करीब पहुंच चुकी है, EV और AI जैसे क्षेत्रों में चीन, अमेरिका से आगे निकल चुका है।

जहां तक सैन्य विस्तार की बात है तो दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और नौसैनिक अड्डे बनाकर चीन अमेरिकी नौसेना को चुनौती दे रहा है, साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों और श्र–20 लड़ाकों से वायु श्रेष्ठता हासिल की।वहीं रूस और उत्तर कोरिया जैसे अमेरिका–विरोधी देशों को ैब्व् और संयुक्त अभ्यासों से एकजुट कर रहा है। जहां तक कूटनीतिक प्रयास की बात है तो चीन ग्लोबल साउथ में अमेरिकी प्रतिबंधों का विकल्प बन रहा है, अफ्रीका–लैटिन अमेरिका में निवेश से प्रभाव बढ़ा। हालांकि, एशियाई देशों (श्रीलंका, फिलीपींस) को आर्थिक प्रलोभनों से अपनी ओर खींचा, जबकि ट्रंप की नीतियों ने इनकी दुविधा बढ़ाई।

सच तो यह है तकनीकी व प्रौद्योगिकी यानी AI (डीपसीक जैसे टूल्स), 5ळ (हुआवे) और क्वांटम कंप्यूटिंग में नेतृत्व से चीन, अमेरिकी डिजिटल वर्चस्व को कमजोर कर रहा है। यह सब 2026 के वैश्विक जोखिमों (जैसे ताइवान संकट) के बीच तेज हो रहा है। इसलिए अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई तेज करता जा रहा है और उसके बदले हुए अंदाज से उसके समर्थक से ज्यादा विरोधी हतप्रभ हैं।

होली के रंगों में घुलता बंधुता का संदेश

फाल्गुन का महीना आते ही हवा में एक अलग–सी उमंग घुलने लगती है। खेतों में पकती फसल, गांवों की चौपालों पर गूंजते फाग और शहरों की गलियों में सजती रंग–गुलाल की दुकानेंकृसब मिलकर संकेत देते हैं कि होली का पर्व आ गया है। परंतु होली केवल रंगों और उल्लास का उत्सव नहीं है, यह समाज को आत्ममंथन का अवसर भी देता है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर और अपने आसपास फैली दूरियों को पहचानकर उन्हें मिटाने का संकल्प ले सकते हैं। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है। यहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं साथ–साथ सांस लेती हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि समय–समय पर जाति, धर्म और संकीर्ण पहचान के आधार पर समाज में दरारें उभरती रही हैं।

ऐसे में होली का त्योहार हमें याद दिलाता है कि रंगों की तरह ही हमारी पहचानें भी अलग–अलग हो सकती हैं, परंतु उनका उद्देश्य एक सुंदर और समरस चित्र बनाना है।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में "न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता" का जो संकल्प दर्ज है, वह केवल शब्दों का अलंकार नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। बंधुता का अर्थ हैकृएक–दूसरे को अपना मानना,

सम्मान देना और साझा भविष्य की कल्पना करना। यदि समाज में भाईचारा कमजोर होगा, तो समानता और न्याय भी अधूरे रह जाएंगे। इसलिए होली का पर्व हमें संवैधानिक मूल्यों को जीवन में उतारने का अवसर देता है।

आज के दौर में जब सामाजिक और राजनीतिक विमर्श कई बार विभाजनकारी रेखाएं खींचता दिखाई देता है, तब होली का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह पर्व कहता है कि मतभेद स्वाभाविक हैं, पर मनभेद घातक। लोकतंत्र में विचारों की विविधता शक्ति है, कमजोरी नहीं। परंतु जब विचारों का अंतर वैमनस्य में बदल जाता है, तब समाज का ताना–बाना कमजोर होने लगता है। ऐसे समय में रंगों का यह उत्सव हमें संवाद, सहिष्णुता और सहभागिता का मार्ग दिखाता है।

ग्रामीण भारत में होली अक्सर सामाजिक मेल–मिलाप का माध्यम बनती है। चौपाल पर बैठकर गाए जाने वाले फाग केवल गीत नहीं होते, वे सामूहिकता की धुन होते हैं। शहरों में भी मोहल्लों और कॉलोनियों में लोग एक–दूसरे के घर जाकर रंग लगाते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि पड़ोसी केवल भौगोलिक निकटता नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्ते का नाम है। यदि हम इस भावना को वर्षभर बनाए रखें, तो समाज में अविश्वास की जगह विश्वास पनप सकता है।

हालांकि यह भी आवश्यक है कि हम होली के उत्सव को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ मनाएं। किसी पर जबरन रंग डालना, अशालीन व्यवहार करना या किसी की धार्मिक–सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, होली की भावना के विपरीत है। बंधुता का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों की सहमति और गरिमा की अनदेखी करें। असली भाईचारा वही है जिसमें सम्मान और मर्यादा दोनों शामिल हों।

स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों को भी इस अवसर का उपयोग संवैधानिक चेतना के प्रसार के लिए करना चाहिए। यदि होली के कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन हो, सामाजिक समानता पर चर्चा हो और जाति–धर्म से परे एकता का संदेश दिया जाए तो यह त्योहार नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है।

पंचायत और स्थानीय संस्थाएं "सद्भाव होली" जैसे आयोजनों के माध्यम से विभिन्न समुदायों को एक मंच पर ला सकती हैं।

आज जब डिजिटल युग में अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, तब सामा. जिक सौहार्द बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह शांति और सद्भाव का दूत बने। होली के अवसर पर यदि हम यह संकल्प लें कि हम न तो घृणा फैलाएंगे और न ही किसी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा देंगे, तो यह पर्व अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करेगा।

हमें यह समझना होगा कि संविधान केवल न्यायालयों और संसद तक सीमित दस्तावेज नहीं है। वह हमारे दैनिक जीवन का मार्गदर्शक है। जब हम किसी को उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उसकी मानवता से पहचानते हैं, तब हम वास्तव में संवैधानिक मूल्यों का पालन कर रहे होते हैं। होली हमें यही सीख देती हैकृरंग भले अलग हों पर मन एक होना चाहिए।

इस वर्ष होली को केवल परंपरा के निर्वहन तक सीमित न रखें। इसे सामाजिक परिवर्तन का अवसर बनाएं। अपने मोहल्ले, गांव या शहर में ऐसा वातावरण बनाएं, जहां हर व्यक्ति बिना भय और भेदभाव के उत्सव में भाग ले सके। आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि बंधुता और भाईचारे की भावना को जीवन के हर क्षेत्र में उतारेंगे, जाति और धर्म की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठेंगे और संविधान में निहित मूल्यों को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे।

जब रंगों के साथ दिल भी मिलेंगे, तभी होली का वास्तविक अर्थ पूर्ण होगा। तभी यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक मजबूत, समरस और संवैधानिक भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम बनेगा।

5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 5

मॉरीशस और मालदीव में चागोस द्वीप समूह का तनाव क्या भारत को भी प्रभावित करेगा!

मॉरीशस ने मालदीव के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह फैसला चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर मालदीव के बदले हुए रुख के बाद लिया गया है। दोनों ही देश भारत के करीबी मित्र माने जाते हैं, ऐसे में यह विवाद क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा संतुलन के लिहाज से भी अहम हो जाता है।

सवाल यह है कि आखिर चागोस द्वीप समूह को लेकर ऐसा क्या हुआ कि दो दोस्त देशों के रिश्ते इतनी तेजी से बिगड़ गए?

चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित 60 से अधिक छोटे द्वीपों का एक समूह है। यह मॉरीशस से लगभग 2,200 किलोमीटर उत्तर–पूर्व और मालदीव के दक्षिण में स्थित है। इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप डिएगो गार्सिया है।

भौगोलिक स्थिति के कारण यह इलाका सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। यहाँ से मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर नजर रखना आसान हो जाता है। इसी रणनीतिक महत्व के कारण अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान यहाँ अपना एक बड़ा सैन्य अड्डा स्थापित किया।

आज भी डिएगो गार्सिया पर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विदेशी सैन्य ठिकानों में गिना जाता है जिसका इस्तेमाल कई बड़े सैन्य अभियानों में किया जा चुका है।

जानकारी के अनुसार चागोस द्वीप समूह और मॉरीशस दोनों ही लंबे समय तक ब्रिटेन के उपनिवेश रहे। जब 1968 में मॉरीशस को आजादी मिलने वाली थी, तब उससे तीन साल पहले 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस से अलग कर दिया। इसके बाद इस क्षेत्र को 'ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र' नाम दिया गया। मॉरीशस का आरोप रहा है कि यह फैसला उस पर दबाव डालकर लिया गया था और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ब्रिटेन ने इसके बदले मॉरीशस को मामूली मुआवजा दिया, जिसे मॉरीशस ने कभी भी न्यायसंगत नहीं माना। यहीं से

चागोस को लेकर कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई की नींव पड़ी।

डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका की शर्त थी कि वहाँ कोई स्थानीय आबादी नहीं होनी चाहिए।

इसके चलते 1967 से 1973 के बीच ब्रिटेन ने चागोस के करीब 1,500 से 2,000 मूल निवासियों को जबरन वहाँ से हटा दिया। इन लोगों को मॉरीशस और सेशेल्स में बसाया गया, लेकिन उन्हें अपने पैतृक द्वीप पर लौटने की अनुमति नहीं दी गई। यह जबरन विस्थापन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का गंभीर मुद्दा बन गया। दशकों से चागोस के मूल निवासी अपने घर लौटने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है।

मॉरीशस ने चागोस पर अपनी संप्रभुता को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 2019 में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि चागोस को मॉरीशस से अलग करना गैर–कानूनी था और ब्रिटेन को इसे जल्द से जल्द वापस करना चाहिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी भारी बहुमत से इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरीशस की संप्रभुता को मान्यता देने पर सहमति जताई हालाँकि डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य अड्डा लंबी अवधि के पट्टे पर बना रहेगा। यह समझौता मॉरीशस के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया।

जानकारों के अनुसार मालदीव और चागोस के बीच समुद्री सीमा को लेकर पहले से ही विवाद रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ने इस मामले में मॉरीशस के पक्ष में फैसला दिया था और मालदीव की पिछली सरकार ने भी मॉरीशस के दावे का समर्थन किया था लेकिन हाल ही में मालदीव सरकार ने अपना रुख बदल लिया। मालदीव के राष्ट्रपति ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरीशस की संप्रभुता को मान्यता देने से इनकार कर दिया और ब्रिटेन–मॉरीशस समझौते पर भी आपत्ति जताई। उनका दावा है कि चागोस पर मालदीव का दावा ज्यादा मजबूत है और यह उसके समुद्री हितों से जुड़ा मामला है। इसी बदले हुए रुख को मॉरीशस ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ सीधी चुनौती माना।

इसके जवाब में मॉरीशस की कैबिनेट ने मालदीव के साथ सभी राजनयिक संबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में तीखा तनाव आ गया है और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल बढ़ गई है।

चागोस द्वीप समूह का विवाद केवल दो देशों के बीच सीमा या संप्रभुता की लड़ाई नहीं है। इसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, महाशक्तियों की रणनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे कई जटिल पहलू जुड़े हुए हैं। मालदीव और मॉरीशस के बीच बढ़ता यह टकराव आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दे सकता है।

कथित शराब नीति मामले में अदालत से बरी हुए केजरीवाल, जांच एजेंसी पर प्रश्न चिन्ह

दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में अदालत द्वारा 23 आरोपितों को बरी किए जाने का फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं बल्कि देश की राजनीति और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी व्यापक विमर्श का अवसर है। यह मामला शुरुआत से ही राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप, जांच की दिशा और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चर्चा में रहा है। इस विवाद में महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें एक सिटिंग मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा था। कहने का आशय यह है कि जब कोई सबूत था ही नहीं तो कैसे एक राजनी. तिक पार्टी को खत्म करने का कार्य किया गया।

दिल्ली सरकार की 2021–22 की आबकारी नीति को लेकर यह आरोप लगा कि लाइसेंस देने और राजस्व संरचना में बदलाव के जरिए कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों ने इसे कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला बताया। इसके बाद गिरफ्तारियां, लंबी पूछताछ और राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला। अब अदालत के फैसले ने यह संकेत दिया है कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत हैकृ संदेह का लाभ आरोपी को। ऐसे में बरी होना इस सिद्धांत की पुष्टि भी है।

इस फैसले से आम आदमी पार्टी को निश्चित ही नैतिक और राजनीतिक बल मिलेगा। विपक्ष लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अदालत का यह निर्णय उन आरोपों को नई धार दे सकता है।

वहीं, केंद्र और जांच एजेंसियों के लिए यह आत्ममंथन का क्षण है–क्या जांच की दिशा, साक्ष्यों की गुणवत्ता और अभियोजन की रणनीति पर्याप्त रूप से ठोस थी? इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय अदालत के हाथ में होता है, न कि राजनीतिक मंचों पर चल रही बहसों में। यह लोकतंत्र के उस स्तंभ की मजबूती को दर्शाता है जो आरोपों और प्रत्यारोपों से परे तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित निर्णय देता है।

हालांकि बरी होना कानूनी राहत है लेकिन यह भी जरूरी है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह हो। भविष्य में ऐसी परिस्थितियां न बनें, इसके लिए सरकारों को स्पष्ट नियम, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया और स्वतंत्र ऑडिट तंत्र को और मजबूत करना होगा।

शराब नीति प्रकरण ने यह सिखाया है कि लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है पर उन्हें साबित करना कठिन। अंततरू कानून की कसौटी पर वही टिकता है, जो तथ्यों और साक्ष्यों से पुष्ट हो। अदालत का यह फैसला राजनीतिक हलकों में चाहे जितनी हलचल पैदा करे, पर लोकतंत्र के लिए यह संदेश स्पष्ट हैकृन्याय की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, पर निर्णायक वही होती है।लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि है।

अदालत का निर्णय यह संदेश देता है कि केवल आरोप या राजनीतिक दबाव किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते; ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। यदि जांच एजेंसियां पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकीं, तो यह उनकी पेशेवर क्षमता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न है। साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य होती है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियां न केवल कानूनी रूप से सुदृढ़ हों, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी स्पष्ट हों।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए नैतिक बढ़त का अवसर बन सकता है। विपक्ष पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप और मुखर होंगे। वहीं केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आत्ममंथन करना होगा।

बार–बार ऐसे मामलों का अदालत में टिक न पाना जनता के मन में अविश्वास पैदा करता है।

खाड़ी युद्ध में किसके साथ खड़ा भारत

अमेरिका–इस्राएल का ईरान से युद्ध भयानक रूप ले चुका है। लगभग पूरा मध्य एशिया इसकी चपेट में आ गया है। अमेरिका जब ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा था, तब ईरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो हर उस जगह हमला करेगा, जहां से उस पर हमला होगा। उसका स्पष्ट इशारा अरब देशों की तरफ था, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। अरब देशों को लगा कि अगर अमेरिका ने उनके देशों के अपने एयर बेस से ईरान पर हमले किये तो वो बेमतलब इस युद्ध में फंस जाएंगे। ईरान की मिसाइल पावर से भयभीत अरब देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोक दिया। अमे. रिका ने इस्राएल और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया था, लेकिन जवाब में ईरान ने अरब देशों के अमेरिकी अड्डो पर हमला कर दिया। ईरान का हमला अमेरिकी अड्डों तक सीमित रहता, तो भी अरब देशों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन अब ईरान अरब देशों के नागरिक और आर्थिक ठिकानों पर हमले कर रहा है। जहां एक तरफ यूएई का आर्थिक स्रोत दुबई उसके निशाने पर है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ अरामको को बर्बाद कर रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान पर भी ईरान हमले कर रहा है। देखा जाए तो अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने से रोकना ही अरब देशों को भारी पड़ गया है। अरब देशों की इस सोच के कारण अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया, इसके बावजूद ईरान ने उनको निशाना बनाया है।

समस्या यह है कि ये देश अपनी सुरक्षा करने के काबिल नहीं हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हैं। इनकी यही निर्भरता आज इन पर भारी पड़ रही है। ईरान इन देशों पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है और ये रोक भी नहीं पा रहे हैं। ये पूरी तरह से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर हैं, लेकिन ईरान के हमले के सामने ये सिस्टम फेल हो गया है। ईरान एक बार में इतनी मिसाइलें मारता है कि उनको रोक पाना सम्भव नहीं होता। देखा जाए तो अरब देश अपनी बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। समस्या यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों की ऐसी हालत कर दी है कि अब इन देशों की सुरक्षा के लिए इन अड्डों का इस्तेमाल भी करना मुश्किल होगा।

एक तरफ इतना भयानक युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में अलग तरह की राजनीति चल रही है। विपक्षी दल बार–बार सरकार से पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में वो किसके पक्ष में खड़ी हुई है। ईरानी नेता खामनेई की मौत पर सरकार द्वारा ईरान से संवेदना प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है। विपक्षी दल दबाव बना रहे हैं कि सरकार खामनेई की हत्या के लिए अमेरिका और इजराइल की निंदा करे। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का एक बड़ा सच है कि वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं होते। वो हर मामले में सोच–समझकर ही कदम आगे बढ़ाते हैं। घरेलू राजनीति में उनका यही रवैया है कि वो समय आने पर ही जवाब देते हैं। वैश्विक राजनीति में तो सारी दुनिया देख रही है कि वो हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वो सही वक्त आने पर ही बोलते हैं, अन्यथा चुप रहते हैं। टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के दर्जनों बयानों के बाद भी उन्होंने चुप्पी बनाये रखी । ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने वाले बयान पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी यही चुप्पी उनके दुश्मनों को परेशान कर देती है। मोदी ने न तो ईरान पर हमले पर कोई बयान दिया है और न ही ईरानी नेता की हत्या पर उनका कोई बयान आया है। वैसे भी देखा जाए तो खामनेई किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, इसलिए उनकी मौत पर कोई बयान देना जरूरी नहीं है। राजनीति में कहा जाता है कि कई बार कुछ नहीं बोलना भी बहुत कुछ बोलना होता है, मोदी इस कला में माहिर हैं । विपक्ष की सारी सोच और राजनीतिक मुस्लिम तुष्टिकरण का शिकार है । विपक्ष खामनेई की मौत पर इसलिए शोर मचा रहा है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम रहते हैं। शिया मुसलमान खामनेई को अपना धर्मगुरु मानते हैं और उनके साथ उनकी भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। खामनेई की हत्या पर सारी दुनिया के शिया मुसलमान बहुत दुखी और परेशान हैं। इसके विरोध में वो पूरी दुनिया में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत का विपक्ष चाहता है कि उनकी भावनाओं को समझते हुए भारत ईरान के साथ खड़ा हो जाये।

मोदी जब सत्ता में आये थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी नीति केवल 'इंडिया फर्स्ट' होगी। उन्होंने कहा था कि वो केवल भारत के हितों को देखकर ही फैसला लेंगे। ईरान और इस्राएल दोनों ही भारत के मित्र देश हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। ईरान के साथ भारत का लेनदेन का रिश्ता रहा है, जबकि इजराइल के साथ हमारे

रणनीतिक संबंध हैं। बात अगर सिर्फ ईरान और इजराइल की होती तो भारत शायद ईरान के पक्ष में खड़ा हो सकता था, क्योंकि हमला इजराइल द्वारा किया गया है। भारत किसी भी देश पर हमले के खिलाफ है और सारे मुद्दे बातचीत से हल करने का समर्थक है ।

इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल है, इसलिए भारत ईरान के साथ नहीं जा सकता, लेकिन अपना विरोध जता सकता था। समस्या यह है कि ये युद्ध ऐसा रूप ले चुका है कि ईरान का पक्ष लेना देश के हितों से समझौता करना होगा। सवाल यह है कि भारत का हित कहां है। ईरान ने लगभग सभी अरब देशों पर हमला कर दिया है और अरब देशों के साथ भारत के आर्थिक, राजनी. तिक और सामाजिक हित इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब ये युद्ध इजराइल–अमे. रिका और ईरान के बीच नहीं रह गया है, ये अरब देशों का युद्ध बन गया है। अरब देशों में भारत के लगभग एक करोड़ लोग रहते हैं । भारत को उनकी चिंता करनी चाहिए या ईरान से दोस्ती के नाम पर उनके रोजगार और सुरक्षा को खतरे में डाल देना चाहिए। आप विचार करें कि देश का हित किसमें है,एक प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को किसके पक्ष में खड़े होना चाहिए। इस्लामिक संगठन ओआईसी में 56 देश हैं, कोई भी ईरान के समर्थन में नहीं आया है । ईरान के साथ भारत का व्यापार सिर्फ दो बिलियन डॉलर का है और दुसरे पक्ष के साथ 400 बिलियन डॉलर का है । ऐसे में भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसका जवाब स्पष्ट हो जाता है। ईरान में सिर्फ दस हजार भारतीय रहते हैं, क्या सरकार दस हजार लोगों के लिए एक करोड़ लोगों के हितों की बलि चढ़ा दे। चीन और रूस ईरान के सबसे बड़े दोस्त हैं, ईरान ने चीन को सस्ता तेल और रूस को हथियार दिये हैं । उन्होंने निंदा करने के अलावा ईरान के लिए क्या किया है।

मोदी अपनी इंडिया फर्स्ट की नीति का त्याग करके, क्या ईरान के लिए अमे. रिका, इस्राएल, यूरोपीय देशों और अरब देशों के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस देश का विपक्ष भारत की बर्बादी चाहता है, ताकि सरकार को घेरा जा सके। गलत फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाए और फिर परिणामों के लिए सरकार को दोष दिया जाए । जो लोग ईरान को भारत का दोस्त बता रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन जब भी पाकिस्तान का मामला आया है, उसने हमारे खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया है। युद्ध के समय उसने पाकिस्तान को अपनी सीमा से सेना हटाने की सुविधा दी है, ताकि वो पूरी सेना भारत के खिलाफ युद्ध में झोंक सके । ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। ईरान ने अपने ही हज़ारो लोगों की हत्या कर दी है और हज़ारो को जेल में डाला हुआ है। कई आतंकवादी संगठन खड़े किए हुए हैं, जो मासूम लोगों की हत्याएं करते हैं । एक क्रूर तानाशाह के खात्मे के लिए भारत को क्यों अफसोस जाहिर करना चाहिए। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल चाहते हैं कि शिया मुसलमानों की खामनेई के प्रति भावनाओं को देखते हुए भारत को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो बंगलादेशी हिंदुओं की हत्याओं पर चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। कश्मीर घाटी हिंदुओ से खाली कर दी गई, किसी की भावनाएं नहीं भड़की। इनका मतलब यह है कि शियाओं की भावनाओं को देखते हुए भारत पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ले और अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े। मोदी जी ने बहरीन, यूएई और सऊदी अरब से बात करके अपना पक्ष बिना बोले ही बता दिया है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की है।

आज हर देश अपने हितों को देखकर ही फैसले लेता है, भारत का हित अमेरिका, इजराइल और अरब देशों से जुड़ा हुआ है। ईरान पर हमले का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन अरब देशों पर हमले का समर्थन कैसे किया जा सकता है। ईरान बेहद आक्रामक होकर अरब देशों पर हमले कर रहा है, ऐसे में भारत का उनके साथ खड़े होना जरूरी है । भारत ने किसी का पक्ष नहीं चुना है, भारत ने अपना हित चुना है, जो कि हर देश का अधिकार है ।

5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 6

बच्चों पर ज्यादा दबाव और रोक-टोक के भयंकर परिणाम

सच यह है कि ज्यादातर अभिभावक बच्चों के भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं। उनकी शिक्षा, करियर और विवाह तक सारे फैसले खुद लेना चाहते हैं और अपने फैसलों को बच्चों पर थोपना अपना अधिकार समझते हैं। उनका कहना होता है कि हम मां-बाप हैं. बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जियें, इसलिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों का मार्गदर्शन करना हर माता-पिता का अधिकार और कर्तव्य है लेकिन इसकी एक सीमा है। आजकल बच्चे अच्छी शिक्षा के बावजूद मनपसंद रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो विवाह से भागने लगते हैं। बुरी संगत में पड़कर व्यसनों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे हालातों में उनके परिजनों के लिए उनको समझना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों का धीरे-धीरे व्यवहार बदलने लगता है। हम बच्चों को यह दोष देने लगते हैं कि ये बदल गया है लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ऐसा हो रहा है।

वर्तमान हालात बच्चों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं. हमारे लिए इसे समझना बेहद मुश्किल है। आज से 30–40 साल पहले बच्चे का अच्छे नंबर लेकर पास होना उसके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी माना जाता था । अब ऐसा नहीं रहा है. जब शत–प्रतिशत अंक आने लगे हैं तो 90 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र भी फेल मान लिए जाते हैं। देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि शत–प्रतिशत अंक लाने वाला छात्र 80–90 प्रतिशत अंक वाले छात्र से बेहतर हो। किसी भी छात्र के अंक उसकी मेहनत या मेधा के प्रतीक नहीं होते, उसके स्वभाव के प्रतीक भी हो सकते हैं। आजकल बच्चों पर मां–बाप का ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का दबाव होता है।

स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का दबाव भी मां–बाप का होता है। आजकल मां–बाप बच्चों से पूछने लगे हैं कि वो क्या करना चाहता है. फिर उसके अनुसार ही उसे आगे बढ़ने का मौका देते हैं।

सच यह है कि ज्यादातर अभिभावक बच्चों के भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं। उनकी शिक्षा, करियर और विवाह तक सारे फैसले खुद लेना चाहते हैं और अपने फैसलों को बच्चों पर थोपना अपना अधिकार समझते हैं। उनका कहना होता है कि हम मां–बाप हैं. बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जियें, इसलिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों का मार्गदर्शन करना हर माता–पिता का अधिकार और कर्तव्य है लेकिन इसकी एक सीमा है। आजकल बच्चे अच्छी शिक्षा के बावजूद मनपसंद रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो विवाह से भागने लगते हैं। बुरी संगत में पड़कर व्यसनों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे हालातों में उनके परिजनों के लिए उनको समझना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों का धीरे–धीरे व्यवहार बदलने लगता है। हम बच्चों को यह दोष देने लगते हैं कि ये बदल गया है लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चों के बदलते व्यवहार को समझे बिना, उनके ऊपर तरह–तरह से दबाव बनाया जाने लगता है। इस खींचतानी का कई बार बड़ा बुरा परिणाम निकलता है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक 21 वर्षीय बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। विडम्बना यह है कि ये हत्या उसने अचानक आवेश में आकर नहीं की है बल्कि सोच–समझकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है । उसने इसके लिए पूरी योजना बनाई, फिर हत्या की और उसके बाद उसने पिता के शव के टुकड़े–टुकड़े करके जंगल में फेंक दिये। इसके अलावा उसने पिता के शव का एक हिस्सा घर में नीले ड्रम में छुपा दिया। वो ये हत्या करने के बाद सामान्य बना रहा और खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है. आरोपी के पिता मानवेन्द्र सिंह एक पैथोलॉजी लैब के मालिक थे. इसके अलावा भी उनके दूसरे व्यवसाय थे। वो अपने बेटे और बेटी के साथ रहते थे, उनकी पत्नी का नौ साल पहले निधन हो चुका था। पिता चाहते थे कि बेटा नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाये लेकिन बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। उसने कई बार पिता को मना किया था, लेकिन पिता उस पर डॉक्टर बनने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उसने पिता के दबाव से परेशान होकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया।

एक दूसरी ऐसी ही शर्मनाक घटना मुज्जफरनगर में सामने आई है। इसमें दो बहनों ने अपने पिता की रोक–टोक से परेशान होकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। उन्होंने परिवार के सदस्यों को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और इसके बाद पिता को चाकू से गोदकर मार दिया। बड़ी बहन की उम्र 32 साल है और छोटी बहन 16 साल की है, दोनों बहनों ने पूरी योजना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये हत्या भी अचानक आवेश में आकर की गई हत्या नहीं है बल्कि योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या है। दोनों बहनों का पहला गुस्सा तो इस बात को लेकर था कि उनके साथ बेटी होने के कारण भेदभाव किया जाता है।

बेटियों के साथ भेदभाव हमारे समाज के लिए बहुत ही सामान्य बात है लेकिन दोनों बहनें इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पिता बड़ी बेटी के अविवाहित होने पर ताना मारते थे। उनको कुँवारी बेटी का घर बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये पता नहीं है कि बेटी का विवाह क्यों नहीं हो रहा था लेकिन इसके लिए वो अकेली दोषी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो। एक तो विवाह नहीं हो रहा था, उस पर पिता के तानों ने उनको गुस्से से भर दिया और उसने अपने पिता का ही कत्ल कर दिया। इसके अलावा कितनी ही घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें बच्चे अपने ही परिजनों की हत्या कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ दूसरों की हत्या ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आत्महत्या भी कर रहे हैं।

बेटे और बेटियों ने अपने पिता को इतनी क्रूरता से क्यों और कैसे मारा, ये एक अलग मुद्दा है। मेरा मुद्दा यह है कि ऐसे हालात क्यों और कैसे पैदा हो गए कि वो अपने ही पिता के हत्यारे बन गए। अगर ये बच्चे आत्महत्या कर लेते तो क्या घटना इतनी ही गंभीर नहीं होती। बच्चों ने हत्या की या आत्महत्या, दोनों ही घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों के लिए सारे फैसले लेना इतना सामान्य क्यों समझते हैं। उनको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा, ये हम कैसे तय कर सकते हैं। बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है तो क्या हम उसे ताने देना शुरु कर दे। उनके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश हम क्यों करते हैं। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि हर मां–बाप अपने बच्चे का भला चाहते हैं लेकिन सब कुछ वो तय नहीं कर सकते।

बच्चों की समझ और विचार को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हों। जब मेरा बेटा पांचवी कक्षा में पढ़ता था तो मैंने उसका स्कूल बदलवा दिया। वास्तव में दूसरा स्कूल कई मामलों से पुराने स्कूल से बेहतर था, मेरी नजर में मेरा फैसला बहुत सही था जो उसके बेहतर भविष्य के लिए था। मेरा बेटा एक माह तक नए स्कूल में गया और धीरे–धीरे उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने खेलना कम कर दिया, कम बोलने लगा और चुप–चुप रहने लगा। मैं जब उसे स्कूल के गेट पर छोड़कर आता तो वो मेरी आँखों से ओझल होने से पहले मुझे मुड़–मुड़ कर देखता था। उसके चेहरे पर एक स्थायी उदासी घर कर गयी थी। मैं और मेरी पत्नी उसके बदलते स्वभाव से परेशान हो गए। एक दिन हमने प्यार से बैठाकर शांति से पूछा कि बेटा नया स्कूल कैसा है। उसने बताया कि उसका स्कूल में दिल नहीं लगता. उसे स्कूल पसंद नहीं है, कोई उससे दोस्ती नहीं कर रहा। हमें अहसास हो गया कि सात साल तक पुराने स्कूल में रहने का आदी हो गया है, इसलिए उसका दिल नहीं लग रहा है। तब हमने उसे वापस पुराने स्कूल भेजने का फैसला किया जबकि इसका मुझे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हो सकता है कि कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया हो, लेकिन बच्चे की उदासी और बदलते व्यवहार के कारण हमने उसे पुराने स्कूल में भेज दिया ।

जब मैं उसके पुराने स्कूल में दाखिल करके आया तो उसकी पूरी क्लास में उसके वापस आने की खुशी मनाई गई। कुछ दिन में ही मुझे लगा कि मेरा बेटा कहीं खो गया था, जो अब वापस मिल गया है। आज उसी स्कूल से पढ़कर निकला मेरा बेटा एक सरकारी बीमा कंपनी में क्लास वन अधिकारी के तौर पर कार्यरत है ।

हर बच्चे की एक क्षमता और योग्यता है, उसे उसके अनुसार काम करने दे। जबरदस्ती किसी को सफलता नहीं दिलाई जा सकती, जब तक वो खुद न चाहे। बच्चों को उनका काम करने में मदद करें, वो जो भी करना चाहते हैं, उन्हें करने का मौका दे। आज जब गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, तब हर बच्चे से बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपके बस में जितना है, उनका साथ दे, लेकिन जब वो अकेले चलना चाहे तो चलने का मौका दे।

समाज की बातों में आकर अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। कभी शिक्षा के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी विवाह के लिए और कभी बच्चों के लिए पूछकर समाज के लोग परेशान करते हैं, लेकिन आपको अपने हालातों के अनुसार चलना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मदद कर सकते हैं तो ठीक है, बेमतलब बच्चों की शिक्षा, नौकरी और विवाह के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ताने देना तो बहुत ही गलत है, इसका अंजाम हमेशा बुरा निकलता है।

बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट

ममता बनर्जी की एसआईआर रोकने की सारी को. शिशें खत्म होती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि 12 राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से एसआईआर होने के बावजूद बंगाल में इसे रोकने की कोशिश क्यों की गई है। विपक्षी दलों ने एसआईआर का विरोध किया है लेकिन ममता बनर्जी इस विरोध में सारी हदें पार कर गई हैं। सवाल यह है कि वो आखिर इस प्रक्रिया से इतनी डरी हुई क्यों है। वास्तव में उनका डर अपनी जगह सही है क्योंकि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ममता का सारा चुनावी गणित गड़बड़ा जाने वाला है। एसआईआर का विरोध उनकी रणनीति नहीं है बल्कि मजबूरी है।

बिहार में जब एसआईआर चल रहा था, तब भी ममता बनर्जी उग्रता के साथ उसका विरोध कर रही थी। जब उनके ही राज्य में एसआईआर चल रहा है तो उनका विरोध सारी हदें पार कर गया है। उन्होंने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिये हैं लेकिन अब उनकी यह कोशिश उल्टा असर दिखा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उसे केंद्र सरकार की कठपुतली बता रही हैं।

टीएमसी एसआईआर के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट गयी थी लेकिन उसे वहां से निराशा हाथ लगी। इसके बाद ममता सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गयी । सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए ममता बनर्जी खुद वकील के चोगे में वहां इस केस की पैरवी करने पहुँच गयी। उन्हें लगा कि इससे सुप्रीम कोर्ट प्रभावित हो जाएगा लेकिन अब लगता है कि माननीय न्यायाधीशो ने उनकी चाल को समझ लिया है।

ममता लगातार मोदी सरकार पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का आरोप लगाती रही हैं लेकिन अब इसका रास्ता माननीय अदालत ने खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय किया हुआ है कि वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इसे संघीय व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ हैं। वैसे देखा जाए तो उनकी यह नीति सही नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था सोच समझ कर की है।

जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बंगाल में बहुत पहले यह काम हो जाना चाहिए था लेकिन अब ये काम सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। सवाल यह है कि हालात यहां तक कैसे आ गए हैं।

वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी की सरकार को कह दिया है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने सारे वो तथ्य रख दिये हैं जिससे साबित होता है कि

ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बंगाल में एसआईआर हो, इसलिए वो चुनाव आयोग का सहयोग नहीं कर रही हैं। इसके विपरीत वो चुनाव आयोग के काम में अड़ंगा डाल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के तर्कों और तथ्यों से समझ गया है कि ममता बनर्जी एसआईआर होने नहीं देंगी। माननीय अदालत ने राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग का सहयोग न करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ–सुथरी मतदाता सूची जरूरी है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ममता बनर्जी की सारी कोशिशें यही थीं कि चुनाव आयोग अपना काम समय पर न कर पाए और चुनाव पुरानी मतदाता सूची के अनुसार ही हो जाये। उन्होंने यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाकर कही थी कि चुनाव आयोग समय पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव करवाने का आदेश दिया जाए। देखा जाए तो ममता बनर्जी ने ऐसे हालात पैदा किये जिससे चुनाव आयोग अपना काम न कर पाये और उसके बाद उसे पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़े। चुनाव आयोग पहले ही 58 लाख मृतक, अनुपस्थित और स्थांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा चुका है।

बंगाल की समस्या यह है कि वहां डेढ़ करोड़ मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा तार्किक विसंगतियों की एक सूची बनाई गई है जिसमें से अभी भी 45 लाख से ज्यादा मतदाताओं के मामलों का निपटारा किया जाना है। इस काम के लिए चुनाव आयोग ने ममता सरकार से ग्रुप ए अधिकारियों की सूची मांगी थी, जिन्हें इन मामलों के निपटारे का काम सौंपा जा सके, लेकिन ममता सरकार ने आयोग को इंतजार करने के लिए कह दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार द्वारा ग्रुप ए अधिकारी उपलब्ध न करवाने की बात कही। माननीय अदालत ने बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि वो आयोग को एसआईआर में मदद के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अधिकारी उपलब्ध करवाए। अदालत के आद.श के बावजूद ममता सरकार ने आयोग को ये अधिक.ारी नहीं दिये और बाद में ग्रुप बी अधिकारियों की एक सूची भेज दी। आयोग का कहना है कि तार्किक विसंगतियों का मामला जटिल है, इसके लिए ग्रुप ए अधिकारी ही सही हैं, ग्रुप बी अधिकारियों से ये काम नहीं करवाया जा सकता।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार के रवैये और चुनाव आयोग से सहयोग न करने पर माननीय अदालत ने निराशा जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मामले की संवेदनशीलता को समझने की सलाह दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो आज से पहले कभी नहीं सुनाया था।

इस फैसले से साबित हो गया है कि माननीय अदालत को सिर्फ राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है बल्कि राज्य की व्यवस्था से भी विश्वास खत्म हो गया है। माननीय अदालत को राज्य के अधिकारियों पर राज्य सरकार का दबाव नजर आ गया है और उसे लगता है कि ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर सकते। माननीय अदालत ने चुनाव आयोग का काम करवाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्यन्यायधीश को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग की तार्किक विसंगतियों के मामले का निपटारा करने के लिए वो जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश उपलब्ध करवाएं। ये न्यायिक अधिकारी सभी जिलों के तार्किक विसंगतियों के मामलों का निपटारा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी है, ऐसे में न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय को शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

देखा जाए तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जो भविष्य में अन्य सरकारों को एक चेता.वनी के रूप में उपस्थित रहेगा। चुनाव आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं होता . वो अपने सभी कामों के लिए संबंधित सरकारों से ही स्टाफ लेता है। इससे राज्य सरकारों को लगता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से उन पर निर्भर है।

देखा जाए तो राज्य सरकारें चुनाव आयोग का सहयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होती हैं लेकिन कई बार वो चुनाव आयोग के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस आदेश ने साबित कर दिया है कि अगर कोई सरकार संवैधानिक कार्यो में बाधा उत्पन्न करती है तो अदालत ऐसा आदेश भी दे सकती है। न्यायिक अधिकारी किसी भी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते । राज्य सरकार न तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकती है और न ही उनका स्थानांतरण कर सकती है। जो अधिकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, उन पर दबाव बनाया जा सकता है लेकिन न्यायिक अधिकारी राज्य सरकार के हर दबाव से मुक्त हैं।

5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 7

लद्दाख की खूबसूरत वादियां

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों, बर्फीली घाटियां, शांत वातावरण, अनूठी संस्कृति, कलात्मक शैली, शिल्प कला और रीति-रिवाजों के लिए विश्व भर में मशहूर है।

लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्व में जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाले, लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर से हिमालय तक फैला, लद्दाख को दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है।

यहां पर आश्चर्यजनक गोम्पास (तिब्बती बौद्ध मठ), लहराते प्रार्थना झंडे, सफेद पुते स्तूप, जटिल भित्तिचित्र और लाल वस्त्रधारी साधुओं के समूह दिखते हैं। तिब्बतियों जैसी संस्कृति में रचे बसे लद्दाख के लोग मिलनसार हैं और पर्यटकों का स्वागत करते हैं। लद्दाख के पर्यटक स्थलों की बात करें तो इसमें हेमिस, पंगोंग झील, त्सो मोरिरी झील, लेह शहर, नुब्रा घाटी, कारगिल शामिल है। इन स्थलों पर पर्यटक ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों, बर्फीली घाटियों, शांत वातावरण, अनूठी संस्कृति, कलात्मक शैली, शिल्प कला और रीति–रिवाजों के लिए विश्व भर में मशहूर है। यहां की सुन्दर झीलें और मठ, मन को सम्मोहित कर देने वाले परिदृश्य और पहाड़ की चोटियाँ हर किसी का मन मोह लेती हैं। लेह दुनिया की सबसे शांत जगहों में भी शुमार है। यहां ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकोक और रेवेन खूब पाए जाते हैं।

लद्दाख को दो जिलों में विभाजित किया गया है– जिला लेह और जिला कारगिल। लेह अपने सुंदर मठों, शांति स्तूप, कैफे और लेह बाजार के कारण एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। उधर, राफ्टिंग और उच्च ऊंचाई वाली ट्रैकिंग के लिए लद्दाख साहसिक खेलों का मैदान है। यदि आप लेह लद्दाख जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो सर्दियों में जाने से बचें।

दुनियाभर में पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है मथुरा

भगवान कृष्ण की नगरी कहलाई जाने वाला धार्मिक स्थल मथुरा दुनियाभर में पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। यहां भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए विश्वभर से पर्यटक आते हैं।

ये स्थल भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमी से भी जाना जाता है। विशेषतौर होली मानाने के लिए यहां दूर–दूर से लोग आया करते हैं। यहां कृष्ण मंदिर के अलावा कई अन्य जगह भी हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। मथुरा से करीब 56 किलोमीटर की दूरी पर आगरा है।

आप चाहें तो मथुरा के साथ–साथ आगरा भी घूमने जा सकते हैं। वहीं, अगर आप मथुरा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको जिन प्रमुख जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं वहां आप घूमने जा

सकते हैं। अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ही जाएं। कृष्ण जन्मभूमि से ही आपको ये साफ हो गया होगा कि ये कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। बता दें कि इस मंदिर को उसी कारागार के बाहर बनाया गया है जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था।

कहते हैं कि यहां कृष्ण भगवान की शुद्ध सोने से बनी 4 मीटर की मूर्ति थी, जिसको महमूद गजनवी द्वारा चुरा लिया गया था।

मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर है। ये राधा वल्लभ मंदिर के पास स्थित है। बता दें कि भगवान कृष्णा का दूसरा नाम बांके बिहारी भी है। इस मंदिर में बांके बिहारी की मूर्ति काले रंग की होती है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको संकरी गलियों से जाना पड़ेगा।

अगर आप भगवान कृष्ण से संबंधित घटनाएं कलाकृतियां देखना चाहते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर विश्राम घाट के निकट स्थित है। इसका निर्माण साल 1814 में किया गया था। इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, खासतौर पर जन्माष्टमी में यहां ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है।

मंदिर के दर्शन करने के अलावा आप म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं। साल 1974 में मथुरा संग्रहालय का निर्माण किया गया था। इस संग्रहालय का पहले नाम कर्जन म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी था। यहां आप कुषाण और गुप्त वंश से संबंधित कई कलाकृतियां देख सकते हैं। यहां अनोखी वास्तुकला और कई कलाकृतियों हैं, इसका चित्र भारत सरकार के स्टैंप पर भी छापा गया है। मथुरा के प्रमुख स्थानों में से एक कुसुम सरोवर है। ये लगभग 60 फीट गहरा और 450 फीट लंबा है। इस सरोवर का नाम राधा के नाम पर रखा गया है। कहते हैं कि यहां भगवान कृष्ण और राधा मिलने के लिए आया करते थे। कुसुम सरोवर में कई लोग नहाने भी आते हैं, यहां का पानी शांत और साफ–सुथरा है। यहां पर होने वाली शाम की आरती यहां का मुख्य आकर्षण केंद्र, कई पर्यटक इस दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद करते हैं।

अगर आप मथुरा घूमने आए हैं तो गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने भी जरूर जाएं। इसका हिन्दू पौराणिक साहित्य में बेहद खास महत्व है।

पौराणिक ग्रंथो के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली से इस पर्वत को उठा लिया था। इस पर्वत का दर्शन करने वाले लोग इसके चक्कर जरूर लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करना अच्छा होता है और भगवान कृष्ण की खास कृपा होती है।

सिंगर बनना चाहती थीं एक्ट्रेस रूही सिंह

मस्ती 4 (2025) फेम एक्ट्रेस रूही सिंह के नाम से एक डबल मीनिंग व्हाट्सऐप चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पिछले दिनों वह काफी चर्चाओं में रहीं। रूही साफ कर चुकी हैं कि ये चौट्स उनकी नहीं हैं और इस सबंध में उन्होंने केस भी दर्ज करवाया है।

हिंदी फिल्मों और टेलीविजन की एक्ट्रेस रूही सिंह एक मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। फेमिना मिस इंडिया ईस्ट 2011 प्रतियोगिता में भाग लेकर रूही सिंह फर्स्ट रनर अप बनीं।

उसके बाद उसी साल उन्हें चीन में आयोजित मिस मॉडल ऑफ़ द वर्ल्ड 2011 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया जहाँ वह टॉप 36 क्वार्टर फाइनलिस्ट में शामिल हुईं।

2012 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया और टॉप 10 में जगह बनाई। उसी साल, मियामी में आयोजित श्मिस यूनाइटेड नेशंस 2012 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

लेकिन रूही को असल सफलता साल 2014 में उस वक्त मिली, जब उन्हें फेमिना मिस इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी 2014 का खिताब जीता।

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया द्वारा रूही सिंह को भारत की टॉप 25 सबसे डिज़ायरेबल वूमेन में से एक (2014) नामित किया गया था। इसके बाद टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020श में वह नवे नंबर पर रहीं।

12 अक्टूबर 1995 को जयपुर में पैदा हुई रूही सिंह का सपना एक सिंगर बनने का था लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी तो साल 2011 में उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और उसके बाद उनकी सारी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गईं।

रूही सिंह कनाडाई एमी–नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड बिफोर हर (2012) में नज़र आ चुकी हैं। इसमें उनके काम से प्रभावित होकर बॉलीवुड फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने उन्हें अपनी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स (2015) की पांच लीडिंग लेडीज़ में से एक के तौर पर साइन किया।इस तरह 25 सितंबर 2015 को रिलीज़ फिल्म कैलेंडर गर्ल्स के जरिए रूही सिंह को अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत करने का अवसर मिला। इसके बाद उन्हें फिल्म इश्क फॉर एवर में देखा गया।रूही सिंह को एम एक्स प्लेयर की सीरीज चक्रव्यूह (2021) और रनअवे लुगाई (2021) की भूमिकाओं के लिए जबर्दस्त लोकप्रियता मिली। चक्रव्यूह (2021) में उनका रोल कई लेयर्स वाला था और उसमें जिस तरह से उन्होंने इंटेंसिटी बनाए रखी वह अपने आप में वाकई लाजवाब था।

रनअवे लुगाई (2021) एक दिलचस्प और मनोरंजक ड्रामा सीरीज़ साबित हुई। इसमें एक छोटे शहर की भागी हुई बोल्ड दुल्हन बुल. बुल के किरदार के लिए न सिर्फ़ क्रिटिकली सराहा गया बल्कि दर्शकों को भी यह सीरीज बेहद पसंद आई।इस सीरीज की कमर्शियल सफलता के अलावा इसमें अदा किए गए किरदार के लिए उन्हें फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के लिए नामांकित किया गया। रूही सिंह उन कुछ कलाकारों में से एक हैं जिनके ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर फैन हैं। अपने अनोखे ग्लोबल स्नैपचौट रिलीज़ के ज़रिए सिंह ने युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और जोश पर 12 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ,उनके शोरू द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम विद रूही सिंह के साथ उनकी लोकप्रियता में जबर्दस्त उछाल आया है।

नागिन 7 में चार चांद लगाएंगी कनिका मान

टीवी का पॉपुलर शो 'नागिन 7' पूरी तरह लोगों के दिलों–दिमाग पर छा चुका है। इस शो में बदला, रहस्य और सुपरनैचुरल ड्रामा, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लगातार ऑडियंस का हुजूम इस शो से जुड़ता चला जा रहा है।कहा जा सकता है कि 'नागिन 7' को इसके पहले 6 सीजन के मुकाबले ऑडियंस का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। इस सीजन के जबर्दस्त लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह शो की कहानी को माना जा रहा है।शो की कहानी इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि हर हफ्ते कोई न कोई बड़ा महाट्विस्ट शो में देखने मिल रहा है। हर नए एपिसोड के साथ कहानी और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। नागिन 7 को उसकी तेज रफ्तार कहानी के लिए भी जमकर तारीफ मिल रही है।शो में नागिन यानी पूर्वी के रोल में प्रियंका चाहर चौधरी का अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेशंस कहानी को काफी मजबूत और असरदार बना रहे हैं।नमिक पॉल के साथ प्रियंका चाहर चौधरी की केमिस्ट्री की खूब चर्चा हो रही है। शो में प्रियंका का किरदार अब सिर्फ एक नागिन तक सीमित नही रहा बल्कि बदले की आग में जलती एक मजबूत महिला के रूप में वह सामने आ रही है। आज के दौर के बेहद कामयाब टीवी शो नागिन 7 में अब कनिका मान की एंट्री ड्रैगन के रोल में होने वाली हैं। शो में इस किरदार की एंट्री पूर्वी यानी नागिन की जिंदगी में बड़ा तूफान लेकर आने वाली है।7 अक्तूबर 1993 को हरियाणा में पैदा हुई कनिका ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी। साल 2015 में उन्होंने मिस कॉन्टिनेंटल का खिताब अपने नाम किया।

संतरे के छिलके की चाय: स्वास्थ्य लाभ, वैज्ञानिक आधार, उपयोग विधि और सावधानियां

–भोला सिंह

संतरे का छिलका, जिसे हम सामान्यतः व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, वास्तव में जैव–सक्रिय तत्वों का समृद्ध स्रोत है। आधुनिक पोषण–विज्ञान और खाद्य–रसायन के कई शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि संतरे के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स और आवश्यक तेल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

– पोषण एवं रासायनिक संरचना (वैज्ञानिक आधार)

संतरे के छिलके में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वः विटामिन फ्लेवोनॉयड्स (विशेषकर **Hesperidin Naringin**) लिमोनीन जैसे आवश्यक तेल ,आहार फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम

प्रमुख शोध संदर्भः इस अध्ययन में पाया गया कि सिट्रस फलों के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता गूदे की तुलना में अधिक सघन हो सकती है।

शोध में दर्शाया गया कि संतरे के छिलके में उपस्थित फ्लेवोनॉयड्स सूजन–रोधी प्रभाव दिखा सकते हैं।

इस अध्ययन ने सिट्रस छिलकों में उच्च फेनोलिक यौगिकों की उपस्थिति को रेखांकित किया।

हेस्पेरिडिन के संभावित हृदय–संरक्षक **cardioprotective** प्रभावों पर चर्चा की गई।

–संभावित स्वास्थ्य लाभ

1. रोग प्रतिरोधक क्षमता

विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन दे सकते हैं।

2. पाचन स्वास्थ्य

फाइबर और जैव–सक्रिय तत्व गैस, सूजन और हल्की कब्ज में सहायक हो सकते हैं।

3. सूजन–रोधी प्रभाव

फ्लेवोनॉयड्स शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

4. हृदय स्वास्थ्य

कुछ अध्ययनों के अनुसार, हेस्पेरिडिन स्क्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकता है।

5. सर्दी–जुकाम में राहत

गर्म चाय गले को आराम देती है और आवश्यक तेल हल्के कफ में सहायक हो सकते हैं।

–बनाने की विधि

ताज़े छिलके सेः

संतरे को अच्छी तरह धोएं

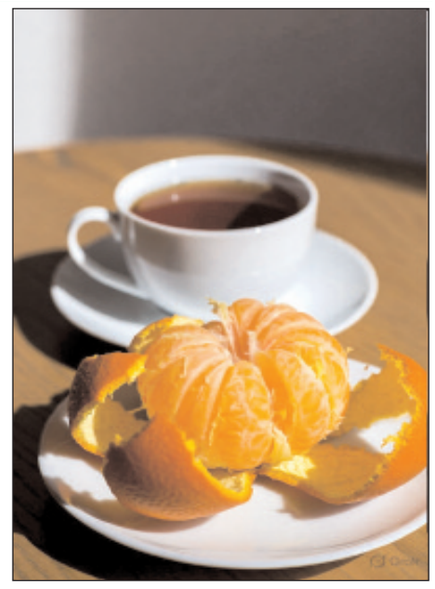

पतला छिलका निकालें

2 कप पानी में 8–10 मिनट उबालें

छानकर सेवन करें

सूखे छिलके सेः

2–3 दिन धूप में सुखाएं

1 चम्मच छिलका 1) कप पानी में 10 मिनट उबालें

छानकर पिएं

–सुझाव

ऑर्गेनिक संतरे का प्रयोग बेहतर

प्रतिदिन 1–2 कप पर्याप्त

सर्दियों में अदरक के साथ सेवन लाभकारी

–सावधानियाँ

छिलका अच्छी तरह धोना अनिवार्य

अधिक सेवन से अम्लता बढ़ सकती है

गर्भवती महिलाएँ या नियमित दवा लेने वाले व्यक्ति चिकित्सकीय सलाह लें

एलर्जी होने पर सेवन रोक दें

निष्कर्ष–संतरे के छिलके की चाय पर उपलब्ध वैज्ञानिक शोध यह संकेत देते हैं कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉयड्स स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये अध्ययन मुख्यतः प्रयोगशाला या सीमित क्लिनिकल स्तर पर किए गए हैं। इसलिए इसे किसी गंभीर रोग के उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। प्राकृतिक उपाय सहायक हो सकते हैं, परंतु संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और चिकित्सकीय परामर्श का स्थान नहीं ले सकते।

खसखस के बीज हैं गुणकारी

खसखस के बीज अक्सर भारतीय घरों की किचन में पाए जाते हैं। महिलाएं कई तरह की रेसिपी में इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ाया जा सके। यकीनन खसखस से बीज टेस्ट को एन्हॉन्स करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन यह सेहत के लिए भी बेहद गुणकारी है। हृदय समस्याओं से लेकर पाचन, अनिद्रा, मधुमेह सहित कई बीमारियों के इलाज में यह मददगार साबित हो सकता है।

महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए खसखस और उनका तेल बेहद फायदेमंद होता है। एक अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब निषेचित अंडे को गर्भाशय की दीवार से खुद को जोड़ने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन खसखस का तेल इस्तेमाल करने से फैलोपियन ट्यूब में मौजूद ब्लॉकेज दूर हो जाती है, जिससे प्रजनन क्षमता की संभावना बढ़ जाती है। कई शोध यह भी बताते हैं कि खसखस में लिग्निन की उपस्थिति कामेच्छा को बढ़ाती है और यौन स्वास्थ्य को बेहतर होता है।

5 March.. to 11 March.. 2026-New:1.qxd 3/5/2026 6:06 PM Page 8

ऑल इंग्लैंड में नहीं खेलेंगी पीवी सिंधू!

नई दिल्ली (एजेंसी): ईरान– इस्राइल–यूएस के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब खेल जगत पर भी साफ दिखने लगा है। बर्मिंघम में शुरू हो रही प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चौंपियनशिप से पहले भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधू दुबई में फंस गई हैं। खाड़ी क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण वह समय पर इंग्लैंड नहीं पहुंच सकीं हैं और उनके टूर्नामेंट से हटने की आशंका है। बताया जा रहा है कि दुबई में उनके ठहरने के स्थान के पास विस्फोट भी हुआ था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बयान जारी कर कहा, हम स्थिति पर रीयल–टाइम नजर बनाए हुए हैं और जिन खिलाड़ियों को देरी या रूट बदलने की समस्या हो रही है, उनकी मदद के लिए तैयार हैं। सिंधू का पहला मुकाबला थाईलैंड की सुपनिदा कातेथोंग से होना था, लेकिन मौजूदा हालात में उनका कोर्ट पर उतरना मुश्किल नजर आ रहा है।

जहां सिंधू की भागीदारी संदिग्ध है, वहीं लक्ष्य सेन और युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी वैकल्पिक मार्ग से बर्मिंघम पहुंच चुके हैं। लक्ष्य का सामना पहले ही दौर में विश्व नंबर–1 शी यूकी से होगा। महिला एकल में मालविका बंसोड़ को ओलंपिक चौंपियन चेन यूफे से भिड़ना है। उन्नति हुड्डा की फ्लाइट रद्द होने के कारण उन्हें अफ्रीका के रास्ते लंबी यात्रा करनी पड़ी, जिससे जेट लैग का असर पड़ सकता है। पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलयेशिया के खिलाफ अभियान शुरू करेगी।ऑल इंग्लैंड का खिताब अब तक केवल दो भारतीय जीत सके हैं। इनमें प्रकाश पादुकोण (1980) और पुलेला गोपीचंद (2001) शामिल हैं। हाल के वर्षों में साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन उपविजेता रह चुके हैं, लेकिन खिताब अब भी दूर है।

ईरान–इस्राइल–यूएस संघर्ष ने यह दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति का असर खेल आयोजनों पर भी पड़ सकता है। खिलाड़ियों की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था अब बड़ी चुनौती बन चुकी है। सिंधू के अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो भी अबू धाबी में फंस गए। वह इंग्लैंड लायंस के कोच के तौर पर अबू धाबी पहुंचे थे। वहां इंग्लैंड लायंस को पाकिस्तान–ए टीम के खिलाफ वनडे खेलना था। हालांकि, मैच भी रद्द हो गया। बेयरस्टो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मदद की गुहार भी लगाई है।

विश्व चैंपियन गुकेश को मिली हार, अरविंद चिदंबरम ने हराया

प्राग । अरविंद चिदंबरम ने प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स वर्ग के छठे दौर में सटीक रणनीति अपना अपनाकर हमवतन डी गुकेश को हराया जिससे मौजूदा फिडे विश्व चौंपियन अंतिम स्थान पर खिसक गया।अरविंद की जीत का मतलब है कि गुकेश अब लाइव रेटिंग सूची में 20वें स्थान पर खिसक गए हैं। किसी प्रतियोगिता में नहीं खेलने के कारण विश्वनाथन आनंद इस सूची में शामिल नहीं हैं। दिसंबर 2024 में खिताब जीतने के बाद से गुकेश को विश्व चौंपियन का अपना रुतबा बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनवरी 2025 में टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट एकमात्र अपवाद था, जब पहले स्थान के लिए खेले गए टाईब्रेकर में वह हमवतन आर प्रज्ञानंद से हार गए थे। अरविंद ड्रॉ से खुश हो जाते लेकिन गुकेश ने 40वीं चाल में गलती की। अरविंद ने इसका फायदा उठाकर 48 चाल में जीत हासिल कर दी।

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए टीम घोषित

❑ लवलीना और निकहत की अगुआई में उतरेगा भारत

नई दिल्ली (एजेंसी): ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और दो बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन 28 मार्च से 11 अप्रैल तक मंगो. लिया में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 20 सदस्यीय टीम की अगुआई करेंगी। भारत ने एक महीने तक चली गहन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 20 सदस्यीय टीम का चयन किया है। जनवरी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद संभावित खिलाड़ियों को पटियाला में चल रहे राष्ट्रीय शिविर में शामिल किया गया था।

चयन नीति के अनुसार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए चुना जाएगा। इससे इस महाद्वीपीय चौंपियनशिप का महत्व बढ़ गया है। स्पेन में हाल ही में बॉक्सम एलीट चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवलीना (75 किग्रा) महिला टीम की अगुआई करेंगी।

स्पेन में स्वर्ण पदक जीतने वाली अन्य खिलाड़ियों प्रीति (54 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा) और प्रिया (60 किग्रा) को भी टीम में शामिल किया गया है।

मौजूदा विश्व चौंपियन मीनाक्षी (48 किग्रा) और जैस्मीन (57 किग्रा) भी टीम में शामिल हैं। महिला वर्ग में अन्य खिलाड़ियों में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन (51 किग्रा), अंकुशिता बोरो (65 किग्रा), पूजा रानी (80 किग्रा) और अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान (80 किग्रा से अधिक) को टीम में जगह दी गई है।

पुरुषों के वर्ग में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और बॉक्सम चौंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता सचिन (60 किग्रा) टीम की अगुआई करेंगे। उनके साथ आकाश (75 किग्रा) भी शामिल हैं, जिन्होंने स्पेन में स्वर्ण पदक जीता था। विश्वनाथ सुरेश (50 किग्रा), आदित्य प्रताप यादव (65 किग्रा), लो. केश (85 किग्रा), हर्ष चौधरी (90 किग्रा) और नरेंद्र (90 किग्रा से अधिक) टीम में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम– पुरुषः विश्वनाथ सुरेश (50 किग्रा), जदुमणि सिंह मंडेंगबाम (55 किग्रा), सचिन (60 किग्रा), आदित्य प्रताप यादव (65 किग्रा), दीपक (70 किग्रा), आकाश (75 किग्रा), अंकुश (80 किग्रा), लोकेश (85 किग्रा), हर्ष चौधरी (90 किग्रा), नरेंद्र (90 किग्रा से अधिक)।

महिलाः मिनाक्षी (48 किग्रा), निकहत ज़रीन (51 किग्रा), प्रीति (54 किग्रा), जैस्मिन (57 किग्रा), प्रिया (60 किग्रा), अंकुशिता बोरो (65 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), पूजा रानी (80 किग्रा), अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान (80 से अधिक किग्रा)।

देश-दुनिया

जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारूंगा

❑ ट्रंप की ईरान को चेतावनी

वॉशिंगटन (एजेंसी): अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चार से पांच सप्ताह तक सैन्य अभियान जारी रह सकता है, लेकिन वह इससे ज्यादा समय तक के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ष्जरूरत पड़ने परष ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिकों को भेजने से इनकार नहीं करेंगे।

उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि अमेरिका और इजरायल अपने अभियान को आगे बढ़ाने के मद्देनजर वे किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक भाषण के दौरान कहा, आज, अमे. रिकी मिलिट्री ईरान में बड़े पैमाने पर कॉम्बैट ऑपरेशन कर रही है ताकि इस भयानक आतंकवादी

सरकार से अमेरिका को होने वाले गंभीर खतरों को खत्म किया जा सके। उन्होंने आगे कहा, ष्सरकार का पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेजी से और बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इससे अमेरिका और विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए एक बहुत ही साफ, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था... इस तेजी से बढ़ते मिसाइल प्रोग्राम का मकसद उनके न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट को बचाना था और किसी के लिए भी उन्हें इन बहुत ज्यादा मना किए गए न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना बहुत मुश्किल बनाना था।

पश्चिम एशिया में संकट बरकरार

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ताजा हमलों के बाद सोमवार को पश्चिम एशिया में युद्ध ने व्यापक रूप ले लिया। इसके बाद, ईरान और उसके सहयोगी देशों ने इजराइल, खाड़ी देशों और तेल–गैस उत्पादन वाले स्थानों पर हमला किया। हमले बढ़ना, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का मारा जाना, और किसी भी स्पष्ट योजना का न होना इस बात का संकेत है कि यह लड़ाई लंबे समय तक जारी रह सकती है तथा इसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं।

सुजीत कलकल ने बढ़ाया भारत का मान

नई दिल्ली। अंडर–23 विश्व चौंपियन सुजीत कलकल ने मुहामेट मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 65 किग्रा फ्रीस्टाइल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। 23 साल के भारतीय पहलवान ने फाइनल में अजरबैजान के राशिद बाबाजादे को 10–0 से हराया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जॉर्जिया के नीका जकाशविली को 10–0 से हराने और अल्बानिया के एंड्रियो अवदली पर 16–4 की जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करने के बाद सेमीफाइनल में अमेरिका के दो बार के पैन अमेरिकन चौंपियन जोसेफ मैककेना पर 11–0 से शानदार जीत हासिल की।

स्वर्ण पदक जीता
भारतीय पहलवान ने फाइनल में अजरबैजान के राशिद बाबाजादे को 10-0 से हराया।

इस महीने की शुरुआत में क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन जीतने के बाद, यह 2026 यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में सुजीत का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। सुजीत ने एंड्रियो अवदली पर 16–4 से जीत के साथ वार्म अप किया, जिन्होंने बाउट की शुरुआत में भारतीय खिलाड़ी को चार अंक पर पटक दिया था। नीका जकाशविली (जॉर्जिया) अगले 10–0 से हार गए, इससे पहले सुजीत ने जोसेफ मैककेना (अमेरिका) को 11–0 से हराया, यह स्कोर जाग्रेब ओपन के सेमीफाइनल जैसा ही था।

राशिद, जिन्होंने सेमीफाइनल में विटाली अरुजाउ (अमेरिका) के खिलाफ 16–13 से जीत हासिल की थी, वे फाइनल में मुकाबला नहीं कर पाए। सुजीत ने उन्हें 10–0 से हराकर लगातार दूसरा रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक जीता। कुल मिलाकर, यह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज सर्किट में सुजीत का चौथा स्वर्ण पदक था। इससे पहले उन्होंने 2022 जैहैर शघायर और 2025 पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमो. रियल में टॉप स्थान हासिल किया था। इसी कैटेगरी में हिस्सा ले रहे भारत के मोहित कुमार क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए।

57 किग्रा श्रेणी में अंकुश और आतिश टोडकर ने कांस्य पदक तक पहुंचने के लिए रेपेचेज में मुकाबला किया, लेकिन अपने–अपने मैचों में हार गए। इस बीच, सुमित (57 किग्रा), राहुल (61 किग्रा), सिद्धार्थ (70 किग्रा), परविंदर (74 किग्रा), और आर्यन (86 किग्रा) अपने–अपने वेट डिवीजन में मेडल राउंड तक पहुंचने में नाकाम रहे।

नेतन्याहू ने पीएम मोदी का जताया आभार, बोले- साथ देने के लिए शुक्रिया

तेल अवीव (एजेंसी): इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में तनाव के बीच इजरायल का साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत मुश्किल समय में ईरान के साथ है। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की यात्रा पर गए थे। इस दौरान भारत और इजरायल के बीच कई महत्वपूर्ण सौदे हुए थे, जिनमें व्यापार और रक्षा क्षेत्र प्रमुख हैं। रिपोर्ट में बताया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच नेतन्याहू ने इजरायल के बेत शेमेश में ईरानी हमले से तबाह जगहों का दौरा किया। इस दौरान नेतन्याहू एक एक यहूदी प्रार्थना स्थल सिनेगाग भी गए, जहां ईरानी हमले में नौ इजरायली लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान बातचीत में नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल की अपनी टेलीफोन पर हुई बातचीत का जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा कि कल उनकी पीएम मोदी से लंबी बात हुई और इजरायल के साथ खड़े रहने, सच्चाई का साथ देने और भारत के लोगों की गहरी दोस्ती के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

उन्होंने आगे कहा कि इजरायल में पीएम मोदी की बहुत तारीफ की जाती है और उन्हें प्यार किया जाता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ष्मैं बातचीत की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे बात की है, और मैंने इस क्षेत्र और उससे आगे के कई दूसरे नेताओं से भी बात की है।ष

मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए फोन पर बात की। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। भारत शत्रुता शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराता है।"

ईरान की तबाही : अरब से अफ्रीका तक राज करेंगे खलीफा एर्दोगन

अंकारा एजेंसीः अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करते हुए ईरान में भारी तबाही मचाई है। अमेरिका और इजरायल मिलकर उन मुख्य स्तंभों में से एक यानी ईरान को खत्म कर रहे हैं, जिस पर चार दशकों से मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स का पूरा ढांचा टिका रहा है। अमेरिका–इजरायल ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत ईरान की ज्यादातर लीडरशिप को मार दिया है और सैन्य ताकत को कमजोर किया है। ईरान के कमजोर पड़ने से तुर्की की भूमिका बढ़ सकती है,जो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत वाली जगह पर है। ईरान की तबाही से तुर्की के लिए प्रभाव बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

बियॉन्ड द आइडियोलॉजिकल के मुताबिक, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने इस युद्ध पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिकी–इजराइली ऑपरेशन की निंदा करते हुए इसे ईरान की आजादी का उल्लंघन बताया और इस्लामिक दुनिया से लड़ाई रोकने के लिए आगे आने की अपील की।

साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों की भी आलोचना की। एर्दोगन ने अपने विदेश मंत्री, इंटेलिजेंस चीफ और गृह मंत्री को इलाके के देशों के साथ बातचीत करने के लिए कहा है। ये दिखाता है कि

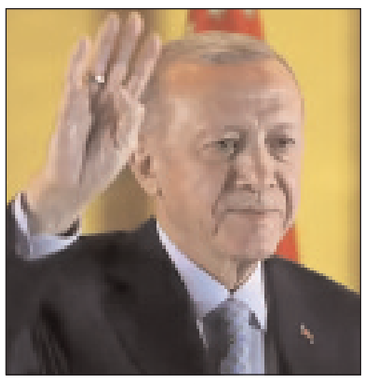

मौजूदा हालात उनके लिए बहुत बड़ा मौका है।

ईरान का कमजोर होना एक ऐसे बदलाव को दिखाता है, जो काफी समय से चल रहा है। दिसंबर 2024 में सीरिया में ईरान समर्थक असद शासन का गिरना इसमें अहम मोड़ था। इससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं का माना जाना और इराक में शिया मिलिशिया नेटवर्क कातिब हिजबुल्लाह के कमजोर होने ने ईरान को झटका दिया। बीते साल तेहरान के इन गुटों के साथ कमांड–एंड–कंट्रोल लिंक टूटे गए।

तुर्की इराकी गुटों के साथ जुड़ाव गहरा करने का मौका दिख रहा है। इसमे कई गुट तुर्की के असर में दिखे हैं, खासकर कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और ईरानी मदद से निराश सुन्नी अरब ग्रुप्स की एक लाइन का रुख तुर्की की तरफ है। सीरिया में तुर्की का असर इन इराकी गुटों को हिम्मत दे रहा है। सीरिया अब बगदाद में अंकारा की स्थिति के लिए स्ट्रेटेजिक मल्टीप्लायर का काम कर रही है।

ईरान के बाद एर्दोगन के लिए दूसरा जरूरी प्लेयर रूस और उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की सीरिया में मजबूत सैन्य उपस्थिति थी, जो असर सरकार कमजोर हो गई। इसके बाद अमे. रिका का ऑपरेशन एपिक रूस की स्थिति और ज्यादा कमजोर कर देगा। ईरान क्षेत्र में रूस का मजबूत साथी रहा है। तेहरान के भविष्य को लेकर अब कई तरह की चिंताएं साफ दिख रही हैं।

रूस के कमजोर होने का फायदा तुर्की के पक्ष में झुक गया है। यह याद रखना चाहिए कि एर्दोगन ने रूस–यूक्रेन झगड़े में तुर्की को एक मीडिएटर के तौर पर खड़ा किया था। बात यह नहीं है कि तुर्की रूस को छोड़ेगा या नहीं। दरअसल अंकारा इतनी तेजी से असर जमा कर रहा है कि एर्दोगन को बातचीत करने के बजाय शर्तें तय करने की इजाजत मिल गई है। ईरान में बदलाव के नतीजे मिडिल ईस्ट से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। खासतौर से तुर्की के लिए बड़ा मौका बनता है।

सैम ऑल्टमैन का बड़ा बयान, पेंटागन का गैर-कानूनी आदेश नहीं मानूंगा

वाशिंटन। एआई की दुनिया में इन दिनों हलचल तेज है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने स्वीकार किया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ हुए समझौते में कंपनी को थोड़ा और समय लेना चाहिए था। बता दें कि यह डील अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ एआई तकनीक के उपयोग को लेकर की गई थी, जिस पर सोशल मीडिया में काफी विरोध देखने को मिला।

मौजूद जानकारी के अनुसार यह विवाद तब और बढ़ा जब एंथ्रोपिक का पेंटागन के साथ अनुबंध समाप्त हो गया। एंथ्रोपिक ने अपनी एआई प्रणाली से कुछ सुरक्षा उपाय हटाने से इनकार किया था, जिसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। इसी के कुछ घंटों बाद ओपनएआई ने पेंटागन के साथ समझौते की घोषणा कर दी, जिसे कई लोगों ने अवसरवादी कदम बताया।

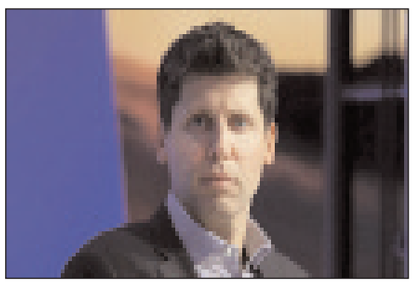

ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माना कि पूरी स्थिति "साफ–सुथरी" नहीं दिखी और इससे गलत संदेश गया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सीखने का अनुभव रहा है, खासकर ऐसे समय में जब फैसले बड़े दांव पर लगे होते हैं। गौरतलब है कि बढ़ते विवाद के बाद ओपनएआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बदलाव किया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसकी एआई प्रणाली का उपयोग अमेरिकी नागरिकों की व्यापक घरेलू निगरानी के लिए नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अमे. रिका के संविधान के चौथे संशोधन, 1947 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और 1978 के फिसा एक्ट जैसे कानूनों के अनुरूप रखा गया है।

ऑल्टमैन ने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी रक्षा विभाग इस सीमा को समझता है और वह जानबूझकर अमेरिकी नागरिकों की ट्रैकिंग या निगरानी के लिए ओपनएआई की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जैसी खुफिया एजेंसियां सीधे तौर पर ओपनएआई की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगी, जब तक कि अलग से संशोधित समझौता न हो।

दिलचस्प बात यह रही कि इस डील के बाद अमेरिका में चौटजीपीटी को अनइंस्टॉल करने की संख्या में तेज उछाल दर्ज किया गया। डेटा फर्म ैमदेवत ज्वूमत के मुताबिक 28 फरवरी को चौटजीपीटी अनइंस्टॉल में करीब 295 प्रतिशत की दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी देखी गई। वहीं दूसरी तरफ क्लॉड की डाउनलोड में 51 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई और यह अमेरिकी एप्पल ऐप स्टोर में नंबर एक पर पहुंच गया

ऑल्टमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से कोई असंवैधानिक आदेश दिया जाता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कानूनी जोखिम उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक अभी कई मामलों में पूरी तरह तैयार नहीं है और सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है।

ABACUS DESIGN STUDIO

SS SERVOSTAR Servo Voltage Stabilizer

Servo Step FOR STRONG TOMORROW